04 - केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की घटती साख

05 - गांधी का सर्व धर्म आज सर्वाधिक प्रासंगिक

A Daily News Magazine

भोपाल

सोमवार, 16 मार्च, 2026

06 - खंडेलवाल निवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

07 - मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हुई किरण के गृहस्थ जीवन की...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 192, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

सवाल नैतिक मूल्यों का : नेहरू और मोदी की दुविधा एक जैसी

प्रवीण स्वामी

साढ़े पांच हजार टन रबर अपने बड़े से होल्ड में पैक करके, पोलैंड का व्यापारी जहाज SS मिकीविक्ज़ कोलंबो में डॉक पर खड़ा था, उसके क्रू मेंबर गर्मी की तेज धूप में तप रहे थे। शंघाई से यांग्त्ज़ी नदी के ठीक ऊपर तियानजिन के लिए मिकीविक्ज़ के निकलने में, नाराज भारतीय अधिकारियों के एक कॉल की वजह से देरी हो गई थी, जिन्होंने क्रू से मुंबई में लोड किए गए इंडस्ट्रियल केमिकल के दो 500 किलोग्राम बैरल ढूंढने और उतारने की मांग की थी। मिकीविक्ज़ के एजेंट्स ने कहा कि यह रिक्वेस्ट पूरी नहीं की जा सकती: कार्गो के लिए फीस दी जा चुकी थी, रिलीज जारी हो चुकी थी, और टाइटल भारतीयों के हाथों से निकल चुका था। जहाज 31 जुलाई, 1953 को सचमुच और लाक्षणिक रूप से रवाना हुआ।

आज–जब आलोचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ईरान संकट पर देश की आजादी और भारत के नैतिक मूल्यों को छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं–डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि उन्होंने जिन मुश्किलों का सामना किया है, वे न तो नई हैं और न ही अनोखी। 1953 में ऐसे ही ऑप्शन का सामना करते हुए, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने उसूलों को किनारे रख दिया था–जैसा कि बाद में हर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ा।

शायद 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' के साथ अपना असर बढ़ाने की उम्मीद में, प्राइम मिनिस्टर नेहरू उसे केरल के अलुवा में इंडियन रेयर अर्थ्स द्वारा माइन और प्रोसेस किया गया थोरियम नाइट्रेट बेचने के लिए मान गए थे। डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड से यह साफ है कि वह उस कीमत के लिए तैयार नहीं थे जो इंडिया को लगभग 40,500 रुपये के एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए चुकानी पड़ी थी–आज लगभग 5.64 मिलियन रुपये।

एसएस मिकीविक्ज़ के कोलंबो से निकलने से तीन दिन पहले, प्राइम मिनिस्टर नेहरू को अमेरिकन एम्बेसडर जॉर्ज एलन ने बताया कि इंडिया को इकोनॉमिक बैन का सामना करना पड़ सकता है। नेहरू ने जवाब दिया कि इंडिया 'कभी भी अपनी नेशनल सॉवरेनिटी के नुकसान के लिए तैयार नहीं होगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का कानून यह तय करे कि इंडिया किसके साथ और किन चीजों में ट्रेड कर सकता है।'

जब वह ये लड़ाई वाले शब्द कह रहे थे, तब भी प्राइम मिनिस्टर पीछे हटने का प्लान बना रहे थे। एक नियम के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी ऐसे देश को मिलिट्री और इकोनॉमिक मदद देने से मना कर देगा जो सोवियत ब्लॉक को 'हथियार, गोला-बारूद, और युद्ध के औजार, एटॉमिक एनर्जी मटीरियल, पेट्रोलियम, स्ट्रेटेजिक वैल्यू वाले ट्रांसपोर्टेशन मटीरियल, और खास स्ट्रेटेजिक महत्व की चीजों' की सप्लाई पर रोक नहीं लगाता।

इस एक्ट ने 18 मई 1951 को यूनाइटेड नेशंस में 47-0 वोट में मदद की, जिससे नॉर्थ कोरिया और चीन को स्ट्रेटेजिक मटीरियल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई। इंडिया समेत आठ देशों ने वोट नहीं दिया। हालांकि, स्ट्रेटेजिक मटीरियल असल में क्या थे, इसकी कोई डेफिनिशन नहीं थी।

नेहरू ने इस दौरान पश्चिम के साथ मिलकर काम किया था। जब भारतीय सैनिक तेलंगाना में कम्युनिस्ट विद्रोहियों से लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वह कम्युनिज्म से लड़ने के लिए एक सीक्रेट कमेटी बना रहे हैं। 1951 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ने लगा था, क्योंकि पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों ही बिना तय सीमा पर अपने दावे करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। नेहरू को शायद ऐसा लगा कि थोड़ा थोरियम बेचने से कुछ बहुत जरूरी फायदा मिल सकता है।

फॉरेन सेक्रेटरी रतन कुमार नेहरू ने 1953 की शुरुआत में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के सामने थोरियम का मुद्दा रखा। प्राइम मिनिस्टर ने 20 फरवरी को जवाब दिया, और कहा कि उन्हें 'अमेरिकन बैन की वजह से विदेश में हमारे सही बिज़नेस पर रोक लगाने का आइडिया पसंद नहीं है। हालांकि मैं साफ़ हूँ कि हमें अमेरिकन बैन की वजह से अपनी एक्टिविटीज़ पर रोक नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मैं इस स्टेज पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मामले और बिगड़ें। मैं थोड़ा इंतज़ार करना चाहूँगा, यह देखने के लिए कि क्या होता है।'

1952 की गर्मियों के आखिर में, US एम्बेसडर चेस्टर बाउल्स ने अभी-अभी रिटायर हुए फॉरेन सेक्रेटरी, गिरिजा शंकर बाजपेयी से देर रात तक कॉन्फिडेंशियल बातचीत की। बाजपेयी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सोवियत यूनियन के बारे में अपने वहम छोड़ दिए थे–भले ही वह 'लंदन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड क्वेकर्स के एक ग्रुप' से प्रभावित रहे हों। भारत कम्युनिस्ट चीन के बारे में धीरे-धीरे बात करता रहेगा क्योंकि उनकी लंबी सीमा एक जैसी है और चीन के हमले का डर है।' बोल्स ने जवाब दिया कि चीन 'भारत की ऊपरी तौर पर दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की कोशिश से नहीं रुकेगा।' कुछ समय बाद, यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी में तैनात एक नेवी ऑफिसर ने बताया कि मुंबई में मिकीविक्ज़ पर थोरियम नाइट्रेट लोड किया गया था। स्टेट डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि यह नई स्थिति 'बहुत गंभीर' थी।

अमेरिका अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से अच्छी तरह जानता था कि थोरियम नाइट्रेट को यूरेनियम के साथ मिलाकर सिविलियन रिएक्टर्स को फ्यूल दिया जा सकता है - जिसमें ट्रॉम्बे में भारत का रिसर्च रिएक्टर भी शामिल है - लेकिन यह न्यूक्लियर-वेपन प्रोग्राम के लिए सही रास्ता नहीं था। बिक्री पर अमेरिका के विरोध के बाद, भारतीय अधिकारियों ने बड़ी चालाकी से ज़िम्मेदारी किसी और पर डाल दी। प्रधानमंत्री ने अपने विदेश सचिव के साथ बातचीत में और राजदूत एलन के साथ बातचीत में ज़ोर देकर कहा कि भारत कभी भी 'अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का अपमान' स्वीकार नहीं करेगा।'

अपनी ओर से, सीनियर एनालिस्ट हंटिंगटन शेल्डन द्वारा किए गए CIA के आकलन से यह नतीजा निकला कि भारत को मदद बंद करने का मतलब होगा 'संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अब दिखाई गई दोस्ताना तटस्थता निश्चित रूप से और भी बुरी हो जाएगी।'

दोनों डेमोक्रेसी के बीच रिश्ते खराब होते गए। 1953 से, यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान के साथ अपना मिलिट्री अलायंस और गहरा कर लिया। नेहरू की तरह, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी उन हालातों के हिसाब से काम चलाना पड़ा जो उनके सामने आए। जैसा कि जर्मन फील्ड-मार्शल हेल्मथ ग्राफ वॉन मोल्टके ने कहा था, 'स्ट्रेटेजी तरीकों का एक सिस्टम है। कुछ ही नैतिक या आइडियोलॉजिकल सिद्धांत असली दुनिया के संपर्क में टिक पाते हैं। मुश्किल समय में, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती जिससे पढ़ा जा सके। लीडर्स को जितना हो सके, खुद को बेहतर बनाना चाहिए, यह जानते हुए कि हर गलती और गलत फैसला बाद में पता चलेगा।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

मैंने पूछा
ये दुनिया ऐसी क्यों है
उसने कहा
ये दुनिया ऐसी ही है,थी और रहेगी
मैंने कहा
क्या तुम भी?
उसने कहा
हां! मैं भी
पर निर्भर करता है तुम पर
मैंने कहा
तो मैं अकेला!
उसने कहा
सब अकेले हैं
तभी तो हमें साथ चाहिए
मैंने कहा
तुम्हारा साथ चाहिए
उसने कहा
मुझे भी तो
मैंने कहा
तो चलो!
उसने कहा
चलो।

– राग तेलंग

चुनाव आयोग ने देश के पांच राज्यों में किया चुनाव का ऐलान

बज गई 'रणभेरी' अब जनता की बारी

- असम-केरल और पुडुचेरी में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग
- तमिलनाडु में 23 अप्रैल,बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग

सभी के नतीजे 4 मई को,सीईसी ने कहा-आचार संहिता हुई लागू

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में सिंगल फेज में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं, बंगाल में दो फेज 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं तीन राज्य केरल, असम और पुडुचेरी में सिंगल फेज यानी 9 अप्रैल वोटिंग होगी। रिजल्ट 4 मई को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने

बताया कि पांच राज्यों- यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए। पहला था एसआईआर, जिसमें यह निश्चित किया गया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में न रहे। दूसरा- मोबाइल फोन बाहर रहेगा।

मतदान केंद्रों के लिए 100 फीसदी वेबकास्टिंग होगी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर 100 फीसदी वेबकास्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया पिछले 12 महीने में चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए कई नए प्रयोग किए।

सीईसी ने कहा-मैं युवाओं से वोट डालने की अपील करता हूं

चुनाव आयुक्त ने कहा-मैं युवाओं और पहली बार वोट देने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। वे वोट जरूर करें।आपका वोट आपकी चॉइस है जो भविष्य का निर्माण करेगा। भारत में चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। चुनाव का ऐलान करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं जो आने वाले चुनाव से जुड़ा है। पांच राज्यों- यूटी में 17.4 करोड़ मतदाता और 824 सीटें हैं। 17.4 करोड़ मतदाता, ऑस्ट्रेलिया,फ्रांस,दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों की कुल आबादी के बराबर हैं।

- होसबोले ने कहा- संघ चाहता है कि दुनिया में शांति हो

भारतीयता-हिंदुत्व मानसिकता नहीं बल्कि जीवनशैली है

पानीपत (एजेंसी)। हरियाणा में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के आखिरी दिन रविवार को सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच ईरान को लेकर भारत के

- दत्तात्रेय होसबाले बोले-ईरान युद्ध पर भारत का स्टैंड सही

स्टैंड पर कहा कि भारत हित में सरकार सही कर रही है, ऐसा विश्वास है कि सरकार का स्टैंड सही है। उन्होंने कहा कि संघ पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देता है। बांग्लादेश और नेपाल में सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद नई सरकारें बनी हैं। दोनों देशों में शांति-स्थिरता और उनका भारत के साथ अच्छा संबंध पूरे एशिया के विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर भी चिंता जताई। होसबाले ने कहा- भारतीयता क्या है, हिंदुत्व क्या है, इसकी एक स्पष्ट अवधारणा होनी चाहिए। यह केवल एक

मानसिकता नहीं बल्कि एक जीवनशैली है। संघ ने अपने तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में आखिरी दिन कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव रखे। इनमें आरएसएस के दायित्व परिवर्तन भी शामिल रहा।

गुरु तेग बहादुर व संत शिरोमणि रविदास जयंती से मैसेज

सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व पर कई कार्यक्रम किए गए। वहीं संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती पर इस साल कार्यक्रम हो रहे हैं। यह समरता का संदेश है। माधव सृष्टि में चल रहे तीन दिवसीय सभा के अंतिम दिन आरएसएस के सरसंघ चालक का संबोधन होगा। इससे पहले दो दिन में आरएसएस की विचारधारा से जुड़े 32 संगठनों ने सुझाव रखे।

दक्षिण के द्वार नेपानगर को बनायेंगे प्रदेश के विकास का प्रमुख द्वार : सीएम यादव

विकास तभी सार्थक, जब इसका लाभ पहुंचे समाज के अंतिम व्यक्ति तक, किसानों की तकदीर बदल देगी नेपानगर की दो सिंचाई परियोजनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नेपानगर अद्भुत नगरी है। यह कृषि और उद्योग का बेजोड़ संगम है। बुरहानपुर जिला मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। हम बुरहानपुर के एग्री एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग का हब बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। प्रदेश के जनजातीय वर्ग का समग्र विकास हमेशा से ही हमारी पहली प्राथमिकता रही है। जनजातीय समाज के समग्र कल्याण के लिए नए वित्त वर्ष 2026-27 के सालाना बजट में 26 प्रतिशत की वृद्धि कर 47 हजार 428 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है, जिससे जनजातीय वर्ग के चहुंमुखी विकास और कल्याण में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय पीएम जन-मन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कराए जा रहे कार्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण का नया

अध्याय लिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को बुरहानपुर जिले के जनजातीय बहुल नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा क्षेत्र को 363 करोड़ 82 लाख रुपए के 127 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 151 करोड़ 62 लाख रुपए लागत के 81 विकास कार्यों का भूमिपूजन (30.59 करोड़ से सातपायरी में औद्योगिक प्रक्षेत्र के भूमिपूजन सहित) और 172 करोड़ 20 लाख रुपए लागत के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकास तभी सार्थक है, जब इसके प्रकाश का पूरा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन विकास कार्यों की सौगात मिली है, यह इस क्षेत्र के जनजातीय बंधुओं के कल्याण में मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतिहास के पन्नों में नेपानगर दक्षिण के द्वार के रूप में अंकित है। कभी खानदेश और दक्षिण की काशी के रूप में पहचाने जाने वाले नेपानगर को हमारी सरकार महाराष्ट्र के छोर पर मध्यप्रदेश के विकास के प्रमुख द्वार के रूप में विकसित करेगी।

- बुछार में ऑपरेशन डिग्गी-2 जारी,पुंछ में ऑपरेशन शेरीकलां के दौरान जवान शहीद

उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर

पुंछ/उरी (एजेंसी)। कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में ऑपरेशन डिग्गी-2 के दौरान एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। यह कार्रवाई तब हुई जब भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास कुछ हलचल देखी। इसके बाद सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन चलाया। 14-15 मार्च की रात बुछार इलाके में घुसपैठ कर रहे आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें आतंकी मारा गया। सेना ने आतंकी के पास से हथियार बरामद किए हैं, जिसमें एक एके राइफल, पिस्तौल और गोला-बारूद शामिल हैं। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। वहीं, शनिवार को पुंछ में जारी ऑपरेशन शेरीकलां के तहत एक जूनियर कमीशंड ऑफीसर शहीद हो गया। जवान का नाम सूबेदार संदीप कुमार ढाका है। व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि ढाका सुरनकोटे के ऊबड़-खाबड़ इलाके में ड्यूटी करते समय फिसलकर गिर गए थे। शेरीकलां के दौरान सुरनकोटे में दोपहर ड्यूटी कर रहे थे।

राहुल के 'चाय-पकौड़े' और शर्टलेस प्रदर्शन पर भड़के शाह

बोले-कांग्रेस ने देश को बदनाम किया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। हाल में हुए एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन और संसद भवन की सीढ़ियों पर कांग्रेस सांसदों द्वारा चाय-पकौड़ा खाने को लेकर अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल के बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करने के प्रयास में देश को बदनाम करने के उनके कृत्यों का कोई भारतीय समर्थन नहीं करता है। अमित शाह ने गुवाहाटी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए

कहा, कभी-कभी वह (राहुल गांधी) संसद के दरवाजे पर बैठकर चाय-पकौड़े खाते हैं, क्या उन्हें एहसास नहीं है कि नाश्ता करने के लिए उचित स्थान क्या होता है। उन्होंने आगे कहा, संसद हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। वहां बैठकर विरोध करना भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आपने विरोध से भी दो कदम आगे बढ़कर चाय-पकौड़े खा लिए हैं। उन्होंने कहा, इससे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है। शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है लेकिन एआई शिखर सम्मेलन एक वैश्विक मंच था न कि निजी राजनीति का अड्डा।

शाह ने किया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन

अमित शाह ने गुवाहाटी में 675 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्राग्ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) का परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन किया। उन्होंने 'असम कैंसर केयर फाउंडेशन' (एसीसीएफ) के तहत गोलाघाट और तिनसुकिया में निर्मित कैंसर केंद्रों का भी ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया। इनमें से प्रत्येक केंद्र का निर्माण 135 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उन्होंने दीफू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (220 करोड़ रुपए), जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (310 करोड़ रुपए) और बारपेटा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (284 करोड़ रुपए) में सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों की ऑनलाइन माध्यम से आधारशिला रखी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 16 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

गाजियाबाद के हरीश इच्छामृत्यु के लिए दिल्ली एम्स हुए शिफ्ट

● घर से आखिरी विदाई, ब्रह्मकुमारी ने टीका लगाया, कहा-सबको माफ करते जाओ

गाजियाबाद (एजेंसी)। 'सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ...ठीक है' यह बातें ब्रह्मकुमारी लवली ने उस हरीश राणा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इच्छामृत्यु की इजाजत दी है। ब्रह्मकुमारी और परिवार के लोगों ने गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन स्थित घर से हरीश को विदाई दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

है। ब्रह्मकुमारी ने हरीश के माथे पर चंदन का टीका भी लगाया। इसके बाद हरीश अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े। इस दौरान हरीश के परिवार के सभी सदस्यों की आंखें नम हो गईं। पिता अशोक ने परिवार के सभी सदस्यों से माफी मांगी। बोले- न चाहते हुए भी यह कदम उठाना पड़ा है। हरीश 13 साल से कोमा में हैं। उन्हें इच्छामृत्यु के लिए शनिवार को दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया है। परिवार ने घर से एम्स तक शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा। पड़ोसी और सोसायटी में रहने वालों को भनक तक नहीं लगी। एक करीबी ने बताया, प्राइवेट गाड़ी से परिवार के लोग हरीश को ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत सम्मानजनक तरीके से एम्स हरीश राणा के जीवन के अंत की व्यवस्था करेगा।

अपने विधायकों को बचाने में जुट गई कांग्रेस पार्टी

● सता रहा हरियाणा-ओडिशा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है। क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के बीच कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की रणनीति अपनाई है। ओडिशा में जहां पार्टी ने अपने 9 विधायकों को कर्नाटक के बेंगलुरु भेज दिया है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस ने अपने विधायकों को शिमला रवाना कर दिया है, ताकि वोटिंग तक पार्टी एकजुट बनी रहे। पार्टी के सूत्रों के अनुसार यह कदम विधायकों को एकजुट रखने और किसी भी तरह के दबाव

या लालच से बचाने के लिए उठाया गया है। बताया गया है कि कांग्रेस के कुल 14 विधायकों में से 9 विधायक बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। वहीं, शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान केवल 5 कांग्रेस विधायक मौजूद थे। इनमें कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता रामचंद्र कदम, वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बहिनिपति, विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दसरथी गमांगो शामिल थे। कदम ने आरोप लगाया कि बीजेपी का इतिहास विधायकों की खरीद-फरोख्त और दल-बदल कराने का रहा है। उन्होंने कहा,बीजेपी और उसकी डबल इंजन सरकार हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल रहने के लिए जानी जाती है। यह उनकी राजनीतिक संस्कृति बन चुकी है। ऐसे किसी भी प्रयास को रोकने के लिए हमारे नौ विधायक बेंगलुरु गए हैं और वहां से दिल्ली जाकर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे।

मनाई गई मां कर्मा देवी की 1010वीं जयंती

भोपाल (नप्र)। साहू समाज की आराध्य देवी मां कर्मा देवी की 1010वीं जयंती राजधानी में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सुबह मां कर्मा देवी का पुष्प श्रृंगार और महाआरती संपन्न हुई। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों, महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या में सहभागिता रही और मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा।

● लक्षद्वीप में बन रहा है प्लांट, 24 घंटे बिजली भी मिलेगी

अब समंदर का पानी पी सकेंगे लोग, बन गया प्लान!

कवरत्ती (एजेंसी)। चारों ओर समुद्र से घिरे द्वीपों की दो सबसे बड़ी चुनौती होती हैं- पीने का मीठा पानी और सस्ती ऊर्जा। लक्षद्वीप में इन दोनों का समाधान समुद्र ही देने वाला है। राजधानी कवरत्ती में ऐसा प्लांट तैयार हो रहा है जो समुद्र के तापमान के अंतर से बिजली पैदा करेगा और उसी प्रक्रिया में समुद्री पानी को पीने के पानी में बदलेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (एनआईओटी) ने ऐसी क्रांतिकारी तकनीक पर काम शुरू किया है, जो इस साल के अंत तक दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगी। यह दुनिया का पहला ऐसा हाइब्रिड प्लांट होगा जो समंदर की लहरों से शुद्ध पानी और चौबीसों घंटे बिजली भी पैदा करेगा। नया प्लांट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन (ओटीईसी) तकनीक पर आधारित है। इसमें समुद्र की सतह का गर्म पानी व गहरे समुद्र का ठंडा पानी इस्तेमाल होगा। गर्म पानी को वैक्यूम में डालकर भाप बनाई जाएगी, यह भाप टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करेगी। फिर गहरे समुद्र से लाए गए ठंडे पानी से भाप को ठंडा करके मीठा पानी तैयार किया जाएगा। नया प्लांट रोजाना 1 लाख लीटर मीठा पानी बनाएगा और जरूरत की बिजली खुद पैदा करेगा। इसे चलाने के लिए डीजल या बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अभी हो रहा लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन तकनीक का इस्तेमाल

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस प्रोजेक्ट को भविष्य की 'ऊर्जा सुरक्षा' का आधार बताया है। लक्षद्वीप के 8 द्वीपों पर पहले से ही लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन तकनीक से पानी बनाया जा रहा है।

ईरान ने दिए लड़ाई में नरमी के संकेत, खाड़ी देशों में हमलों पर सफाई

युद्ध रोकने की किसी भी पहल का स्वागत है

तेहरान (एजेंसी)। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि उनका देश लड़ाई खत्म करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का स्वागत करेगा। अराघची के बयान से ईरान के इजरायल के साथ 28 फरवरी से चल रही लड़ाई में नरम पड़ने के संकेत मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में इजरायल हमले करके इसका दोष ईरान पर मढ़ रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने कतर, सऊदी अरब, ओमान और पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संपर्क बने हुए हैं। अब्बास अराघची ने रविवार को कहा, तेहरान युद्ध खत्म करने की किसी भी पहल का स्वागत करता है, जिससे युद्ध का पूरी तरह अंत हो सके। अराघची का यह बयान ऐसे समय आया

है, जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अपने तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों ने हमले तेज करने की धमकियां दी हैं। अब्बास अराघची ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान ने इस युद्ध में पड़ोसी अरब देशों में किसी भी नागरिक या रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया है।

ईरान-इजरायल युद्ध की तीसरे हफ्ते में एंट्री

इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इसके बाद से लगातार लड़ाई चल रही है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान में भीषण बमबारी की है। इसमें ईरान में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। ईरान में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं तो 1300 से ज्यादा लोगों की जान अब तक हमलों में गई है। ईरान ने अमेरिका-इजरायल गठबंधन के हमलों का जवाब देते हुए खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य बेसों पर मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। वहीं इजरायल में भी लगातार मिसाइल हमले किए गए हैं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को भी बंद कर दिया है। इससे दुनियाभर में तेल सप्लाई प्रभावित है और ऊर्जा संकट गहरा रहा है।

भारत रत्न से सम्मानित किए जाएं काशीराम

राहुल गांधी ने की मांग, पीएम मोदी को लिखा लेटर

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक न्याय आंदोलन के महान नेता कांशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। गांधी ने रविवार को अपने पत्र में कहा कि मान्यवर कांशीराम ने भारतीय राजनीति की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुजन समाज तथा गरीब वर्गों में राजनीतिक चेतना जगाई थी। उनका कहना था कि उनके इन प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई और राजनीतिक व्यवस्था अधिक प्रतिनिधिक तथा न्यायपूर्ण बनी। कांग्रेस नेता ने कहा, आज जब हम कांशीराम जी की जयंती मना रहे हैं और उनके जीवन तथा योगदान को याद कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए।

चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ममता का 'खेला'

चला बड़ा दांव, पुरोहितों और मुअज्जिनों का मानदेय बढ़ाया

कोलकाता (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है लेकिन इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। ममता सरकार ने पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर इसकी जानकारी दी है। सीएम ममता ने घोषणा की कि पुरोहितों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है। इससे यह कुल 2000 रुपये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए

रखने में उनके योगदान को मान्यता देता है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह कदम उन लोगों को सहयोग देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है, जो पूरे राज्य में समुदायों की सेवा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसे धार्मिक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया कार्य समाज में सद्भाव और सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नेपाल में भारतीय तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी

● 7 लोगों की मौत, 7 घायल, मनाकामना मंदिर से दर्शन कर लौटते समय हादसा

काठमांडू (एजेंसी)। नेपाल के गंडकी प्रांत के गोरखा जिले में शनिवार रात भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हैं। यात्री मनाकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक, श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक माइक्रोबस मनकामना मंदिर से लौट रही थी, तभी सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में घायल 7 यात्रियों को भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। पुलिस के अनुसार बस में एक दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। प्रशासन के अनुसार बस मनाकामना मंदिर से तनहुन जिले के अंबुखैरेनी इलाके की ओर जा रही थी।

● 4 दिन तक विस्फोटक का इंतजार करते रहे आरोपी, 3 जगह धमाके की साजिश

राजस्थान में बम ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से भेजा आईईडी

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में बम धमाके के लिए पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी ने साजिश रची थी। बॉर्डर एरिया वाले जिले हनुमानगढ़ में आतंकी ने इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस भी पहुंचा दी थी। आरडीएक्स पहुंचने में देरी से आतंकी साजिश नाकाम हो गई। ये खुलासा हरियाणा के अंबाला में 2 किलो आरडीएक्स, आईईडी व विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़े गए तीन आरोपियों से पूछताछ में हुआ है। इनमें एक आरोपी अजमेर का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार आतंकी

शहजाद भट्टी के इशारे पर ड्रोन के जरिए अमृतसर (पंजाब) में आरडीएक्स व दूसरा सामान भेजा गया था। सुरक्षा एजेंसी के सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरडीएक्स से पहला ब्लास्ट हनुमानगढ़ में किया जाना था।

आंतकी भट्टी ने तीनों आरोपियों को टारगेट बताए

अंतिम टारगेट के रूप में आतंकी शहजाद भट्टी ने तीनों आरोपियों को एक दिन पहले अंबाला के तीन टारगेट बताए और कहा कि इनमें से एक जगह विस्फोट करना है। ये टारगेट थे – मुलाना का माता बाला सुंदरी मंदिर, जहां चैत्र नवरात्रों में हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती है। दूसरा टारगेट अंबाला के एक बड़े नेता का घर और तीसरा टारगेट सैन्य क्षेत्र तोपखाना में स्थित एक सैन्य ठिकाना था।

टाइम मैग्जीन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस में भारत के 4 स्थान

पर्यटकों को लुभा रहे 'जोधपुरी स्ट्रॉबेरी खेत', 7000 फीट की ऊंचाई पर मिल रहा सुकून

न्यूयॉर्क (एजेंसी)। पूरी दुनिया में घूमने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। साल 2025 में करीब 1.5 अरब पर्यटकों ने विदेश यात्रा की, जो पिछले साल से 4 फीसदी अधिक है। इसी उत्साह को देखते हुए 'टाइम' मैग्जीन ने दुनिया के 100 द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 की सूची जारी की है। इसमें भारत के भी 4 स्थानों को शामिल किया गया है। यह लिस्ट अंतरराष्ट्रीय लेखकों और संवाददाताओं के फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें नए और रोमांचक अनुभव देने वाली जगह शामिल हैं।

थार के बीच जोधपुर का 'म्हारो खेत', खेती के साथ लग्जरी स्टे

जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित 'म्हारो खेत' थार रेगिस्तान के बीच एग्री-टूरिज्म का शानदार ठिकाना है। 40 एकड़ के रीजेनरेटिव फार्म पर बने इस परिसर में 10 लग्जरी सुइट्स हैं, जो मेहमानों को प्रकृति और खेती के करीब लाते हैं। यहां का मुख्य आकर्षण खेत की ताजी उपज और स्ट्रॉबेरी-अनार के बागान हैं। मेहमान खुद सब्जियां चुनने के साथ कुकिंग लेसन और फार्म वॉक का आनंद ले सकते हैं। भोजन के लिए यहां 3 रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं।

पहाड़ियों में 'शक्ति प्राण लॉज' पहुंचने का रास्ता सिर्फ पैदल

कुमाऊं। उत्तराखंडके कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित 'शक्ति प्राण लॉज' शांति और रोमांच का अनूठा

संगम है। 7,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस रिट्रीट तक केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है। यहां सौर ऊर्जा से संचालित सिर्फ 7 सुइट्स हैं, जहां से नंदा देवी और पंचाचूली चोटियों के अद्भुत दृश्य दिखते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह खास है, जहां बर्फीली चोटियों के बीच लकड़ी के फायरप्लेस और सुकून भरा वातावरण मिलता है।

पहाड़ियों में लीजिए बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों का आनंद

राजगढ़। मध्य प्रदेश की मणियागढ़ पहाड़ियों में स्थित 'द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस' बुंदेला वंश के 350 साल पुराने निवास को रीस्टोर कर बनाया गया भव्य रिसॉर्ट है। झील के किनारे बसे इस रिसॉर्ट की बड़ी खूबी पन्ना नेशनल पार्क के पास इसकी लोकेशन है, जहां सैलानी बाघ और तेंदुए देख सकते हैं। यहां के विशेषज्ञ मेहमानों को रनेह जलप्रपात और केन अभयारण्य की सफारी कराते हैं।

एएबीबीसीसी-बार नहीं, ड्रिक्स का म्यूजियम जैसा एक्सपीरियंस

नई दिल्ली। दिल्ली के वसंत विहार में स्थित 'एएबीबीसीसी' ड्रिंक्स का एक आधुनिक म्यूजियम है। इसकी शुरुआत एक लैब से होती है, जहां जड़ी-बूटियों और शहद जैसी अनोखी सामग्रियों से पेयों को नया स्वाद दिया जाता है। यहां का मेन्यू समय की यात्रा जैसा है, जो बीता कल, आज और आने वाला कल श्रेणियों में बंटा है।

राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी घेराबंदी तेज

ओडिशा में चौथी सीट पर दिलचस्प मुकाबला

ओडिशा में चार सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। विधानसभा में बीजेपी के 79 विधायक हैं और पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और मौजूदा सांसद सुजीत कुमार को मैदान में उतारा है। बीजद ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी संत्रुप्त मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। चौथी सीट को लेकर मुकाबला सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। इस सीट के लिए बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को समर्थन दिया है।

बिहार-ओडिशा और हरियाणा में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए सोमवार को होने वाले मतदान से ठीक पहले बिहार, हरियाणा और ओडिशा में सियासी हलचल तेज हो गई है। संभावित क्रॉस-वोटिंग और विधायकों की टूट-फूट को रोकने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने-अपने विधायकों की घेराबंदी शुरू कर दी है। कई जगहों पर विधायकों को रिसॉर्ट में ठहराया गया है तो कहीं उन्हें रोजाना पार्टी नेतृत्व के सामने उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। देशभर में इस बार राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इनमें से 26 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं।

बिहार में पांचवीं सीट पर नजर

बिहार में पांच सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जहां संख्याबल के आधार पर एनडीए चार सीटें आसानी से जीत सकता है। एनडीए के पास विधानसभा में कुल 202 विधायक हैं, जबकि एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोट की जरूरत है। एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, जिससे राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा है। इसके अलावा भाजपा के नितिन नवीन, जदयू के रामनाथ ठाकुर और शिवेश कुमार तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीदवार बनाया गया है।

हरियाणा में भी मुकाबला रोचक

हरियाणा में दो सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं और पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर सिंह बौद्ध को भी पार्टी और सहयोगियों के समर्थन से पर्याप्त वोट मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नंदल के मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नंदल को बीजेपी के करीबी के तौर पर देखा जाता है और पिछले चुनावों में कांग्रेस को क्रॉस-वोटिंग का नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे इस बार भी राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है। इस वजह से कांग्रेस के कुछ विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेजा गया है जहां कांग्रेस की सरकार है।

परिक्रमा

स्वास्थ्य बीमा योजना को बेहतर बनाने के प्रयास

अरुण पटेल

लेखक सुबह सवेरे के प्रबंध संपादक हैं

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनएसीपी के तहत मध्यप्रदेश के सात शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए अब साल भर निरन्तर प्रयास जारी रहेंगे। प्रदेश में संस्कारधानी के नाम से जानी जाने वाले जबलपुर में डीप फोगर मशीन का साल भर इस्तेमाल किया जायेगा। जबलपुर शहर को प्रदूषणमुक्त करने की दिशा में नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सघन कार्रवाई की जा रही है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीप फोगर मशीन प्रमुख मार्गों पर चलाई जा रही है इससे धूल के बारीक कण बैठ जाते हैं। वहीं रोजाना सड़क, फुटपाथ और चैराहों की जेट प्रेशर से धुलाई की जा रही है। निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है, लेकिन हालात में कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आया है। इस कार्यक्रम के लिए 15 जनवरी से प्रयास प्रारंभ किये गये हैं। इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर की वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब पाया गया जिसका मुख्य कारण उद्योगों से निकलने वाला धुंआ, वाहनों का प्रदूषण और धूल के कण हैं जो आम लोगों के फेफड़ों के साथ ही आंखों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

इसकी कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गयी हैं जो हर माह वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए इसकी समीक्षा करती हैं। वायु गुणवत्ता सुधार के कार्य से जुड़े विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, परिवहन, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी सफलता उस समय ही सफलीभूत हो पायेगी जबकि पूरी निष्ठा व लगन से मैदानी स्तर पर इसे कार्यानिवत किया जाये। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आयुक्त ए. मिश्रा के अनुसार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत सभी शहरों की सभी सड़कों को डिजाइन निर्माण, रखरखाव तथा यातायात गलियारों के हरित विकास द्वारा धूल नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज जारी कर दिया गया है। ताकि धूलमुक्त सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यह प्रयास भारतीय सड़क कांग्रेस के इंजीनियरिंग मानकों को पर्यावरणीय उपायों जैसे धूल नियंत्रण, वनस्पति एवं जल निकासी के एकीकृत रुप से किये जा रहे हैं ताकि संधारणीय शहरी अधोसंरचना और वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

जहां तक मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य योजना को बेहतर बनाने का सवाल है डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सात लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने के लिए कमर कसती नजर आ रही है। यह पात्रता वित्तीय मॉडल व क्रियान्वयन संरचना को देखने के साथ ही साथ कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन से विचार-विमर्श कर योजना का दस्तावेज तैयार करेगी। इसे पहले मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सदस्यों की समिति के समक्ष रखा जायेगा और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही केबिनेट की बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। सामान्यतः यह देखने में आया है कि योजना तो बड़ी अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन होने में जो उदासीनता बरती जाती है उससे सुविधा के स्थान पर असुविधा ही बढ़ जाती है। प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के समय से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी चल रही है। कई बार विचार-विमर्श भी हो चुका है और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा षिक्षा विभाग ने इस योजना का जो खाका तैयार किया है उसके अनुसार यह अंशदायी होगी। कर्मचारियों से श्रेणी के हिसाब से अंशदान लिया जायेगा जो 250 से 1000 रुपया प्रतिमाह प्रस्तावित है। योजना का संचालन राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किया जायेगा। इसमें कानूनी, बीमा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी होंगे। तकनीकी टीम भी रहेगी जो क्लेम प्रोसेसिंग, हेल्थ पेकेजिंग और अस्पतालों की सम्बद्धता आदि का कार्य देखेगी।

और यह भी ?

डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन स्टेट वन डेस्टीनेशन के अंतर्गत केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के आसपास आर्ट और क्राफ्ट विलेज के निर्माण के लिए 200 एकड़ ग्रीनफील्ड का प्रस्ताव भेजेगी। जिससे खजुराहो क्षेत्र को आर्ट एण्ड क्राफ्ट विलेज के रुप में विकसित किए जा रहे गांवों में समरुपता की दृष्टि से प्रयास किये जा सकें। आसपास के डेम और जलप्रपातों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जायेगा ताकि इसे पर्यटन से जोड़कर लाभ का कारोबार बनाया जा सके। अभी यह काम मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम करता है जिससे स्थानीय स्तर पर दिक्कतें आती हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि खजुराहो में प्रतिवर्ष औसतन 38 हजार विदेशी पर्यटक आते हैं, इनकी संख्या और ठहरने की अवधि बढ़ाने की दृष्टि से पर्यटन सुविधाओं में विस्तार किया जायेगा। इस प्रकार मध्यप्रदेश सरकार अब पर्यटन से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ायेगी।

द्वितीय दिवस पर श्रीराम जन्म धूमधाम से मनाया

भोपाल। मैहन्दीपुर बालाजी मंदिर परिसर, प्राईवेट बिजली नगर कालोनी, गोविंदपुरा, भोपाल में आज द्वितीय दिवस राम जन्म धूमधाम से मनाया, कथा के द्वितीय दिवस यजमान दिनेश दरबार (बब्बू भाई) और उनकी पत्नी व्यवस्थापक हरी कुमार व्यास, सुभाष व्यास, अनूप राजपूत, रोहित चौबे, लक्ष्मी नारायण पंथी, अशोक दीक्षित, आर सी नायक, श्रीमती संध्या शर्मा, सत्येन्द्र मोहन स्रोती, वरूण शर्मा, अमन, लाल चंद मेहरा, राम मोहन शर्मा ने पूजा

श्रीमती विभा दरबार ने पूजा अर्चना की उसके पश्चात श्री रामकथा व्यास गादी पर विराजमान पं. राम नरेश जी चौबे के मुखारविंद से अमृत वाणी से श्री राम कथा का वाचन किया गया।

मुख्य यजमान रोहित चौबे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सूर्या चौबे ने व्यास गादी का पूजन किया, अर्चना की । आयोजन में कालोनी की सम्माननीय महिलाओं और पुरुषों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई।सभी धर्म प्रेमियों से अनुरोध हैं श्री राम कथा दिनांक 14-03-2026 से दिनांक 18-03-2026 तक समय 3.30 दोपहर से शाम 6.30 तक नियमित रूप से श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित करे।

इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में बनेंगे 'गीता भवन' : मुख्यमंत्री

100 निकायों में भूमि उपलब्ध, 4 शहरों में ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर और जबलपुर की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन बनाएँ जा रहे हैं। गीता भवन के माध्यम से दार्शनिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास है। इन केन्द्रों में युवा पीढ़ी को गीता के निष्काम कर्म और भारतीय मूल्यों से जोड़ने और शोधार्थियों के लिए विशेष संसाधन उपलब्ध कराना गीता भवन का मुख्य उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को विस्तार देने के लिए गीता भवन परियोजना को अब वृहद स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के सभी 413 शहरों में गीता भवन निर्माण की योजना के लिए 5 वर्षीय कार्ययोजना के वर्ष 2026-27 के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में भारतीय दर्शन, कला और साहित्यिक विमर्श के लिए एक आधुनिक अवसंरचना तैयार करना है। इंदौर और जबलपुर में निर्मित गीता भवन की सफलता को आधार मानते हुए अब इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

4 शहरों में प्रोजेक्ट्स स्वीकृत, 100 निकायों में भूमि चिन्हांकित

योजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विभाग ने चार प्रमुख शहरों में ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें रीवा (5 करोड़ रुपये), छिंदवाड़ा (2.5 करोड़ रुपये), कटनी (2.4 करोड़ रुपये) तथा खंडवा (2 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 6 नगर निगमों सहित 100 नगर पालिकाओं में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है, जिनकी डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शेष 313 नगरीय निकायों में भी भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है और जिला कलेक्टरों के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है।

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे सांस्कृतिक केंद्र

प्रत्येक गीता भवन को एक बहुउद्देश्यीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके प्रमुख घटकों में अत्याधुनिक ऑडिटोरियमः वृहद स्तर पर सांस्कृतिक एवं वैचारिक आयोजनों के लिये ज्ञान का केंद्रः ज्ञानार्जन के लिए समृद्ध लाइब्रेरी एवं हाई-टेक ई-लाइब्रेरी। व्यावसायिक एवं जन-सुविधाएंः कैफेटेरिया और विशेष रूप से पुस्तकों एवं आध्यात्मिक सामग्री के लिए समर्पित विक्रय केंद्र शामिल हैं।

निबंध तथा पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत

सशक्त एवं जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव : खाद्य मंत्री राजपूत

खाद्य मंत्री ने देखी मिलावट : पीली हल्दी हो गई लाल, बोले- मिलावटखोर धीमा जहर दे रहे, हर उपभोक्ता जिद्दी बने

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने सभी को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि एक सशक्त और जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव होता है। श्री राजपूत ने कहा कि खाद्य पदार्थों के रूप में धीमा जहर देने वाले के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करें, तभी इस दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो, यह हमारा दायित्व भी है और संकल्प भी है।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि खरीददारी करते समय बिल लेना, उत्पाद की गुणवत्ता और समाप्ति की तिथि अवश्य देखना, किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराना, यह सभी जागरूक उपभोक्ता को मजबूत बनाते हैं।

उपभोक्ताओं के हित में भारत सरकार ने वर्ष 2019 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। यह कानून उपभोक्ताओं के रक्षा की गारंटी देता है। इसमें 06 प्रकार के अधिकार चुनने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, उपभोक्ताओं की सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की समस्याओं के निराकरण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (जागरूक बने रहने का अधिकार) बताये गये हैं। श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध हैं। भ्रामक खबरों से सावधान रहें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वर्तमान परिस्थितियों में बड़े आयोजनों से बचें।

चौंक गए मंत्री

कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सभागार परिसर में लगी एक विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट और उसकी पहचान के तरीकों के बारे में बताना था।

पुरस्कार

कार्यक्रम में वर्ष 2025 में बेहतर कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। संस्थाओं में 1 लाख 11 हजार रूपये का प्रथम पुरस्कार अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन कटनी को तथा 51 हजार रूपये का द्वितीय पुरस्कर प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय समिति ग्वालियर को दिया गया। पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार उज्जैन की कु. अश्विता पोरवाल, द्वितीय इंदौर की कु. रानी चौधरी तथा तृतीय पुरस्कार छतरपुर की कु. खुसबू रैकवार को मिला। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार छतरपुर की कु. शुभि सेन, द्वितीय छतरपुर की ही कु. तपस्या कुशवाह और तृतीय पुरस्कार धार की कु. पलक सिसोदिया को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ स्टॉल का पुरस्कार भारतीय खाद्य निगम, द्वितीय पुरस्कार म.प्र. वेयर हाउसिंग और तृतीय खाद्य एवं औषधि प्रशासन को मिला।

कार्यक्रम में प्रदर्शनी के माध्यम से उपभोक्ताओं को मिलावट की पहचान, उपभोक्ताओं के अधिकार, औषधि क्रय एवं उपयोग में सावधानियां आदि विषय पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। आभार प्रदर्शन संयुक्त संचालक श्री हरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान आयुक्त नागरिक आपूर्ति निगम श्री अनुराग वर्मा, नियंत्रक नापतौल श्री बृजेश सक्सेना, आयोग के सदस्य श्री नेमी जैन और सुखदेव मिश्रा सहित उपभोक्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

जिला उपभोक्ता आयोग में 14 हजार से अधिक मामले निराकृत

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि राज्य उपभोक्ता आयोग में वर्ष 2025-26 तक लगभग 3 हजार मामलों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार जिला उपभोक्ता आयोग में 14 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। राज्य उपभोक्ता आयोग में दिसंबर, 2020 से अभी तक 7 हजार 5 सौ से अधिक मामले ऑनलाईन दर्ज किये गये। जिला उपभोक्ता आयोगों में 26 हजार से अधिक मामले ऑनलाईन दर्ज हुये। सदस्य राज्य उपभोक्ता आयोग डॉ. मोनिका मलिक ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सुरक्षित उत्पाद-सशक्त उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुल 2574 मामले निराकृत हुए जबकि 2285 नये मामले दर्ज किये गये। आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री कर्मवीर शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिये यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस प्रदर्शनी में यह बताया गया कि किस खाद्य पदार्थ में कैसे मिलावट होती है और उसे कैसे पहचान सकते हैं। इसी दौरान एक स्टॉल पर मंत्री ने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे हल्दी में मिलावट की जाती है। स्टॉल पर मौजूद कर्मचारी ने केमिकल में जैसे ही हल्दी डाली तो उसका रंग पीले से लाल हो गया। ये देखकर मंत्री चौंक गए। फिर उन्होंने अपने संबोधन में इसका जिक्र किया।

फर्जी बिलिंग से जुड़ा है मामला, 2 दिन पहले अपर आयुक्त पर दर्ज हुई थी एफआईआर

फाइनेंशियल गड़बड़ियों को लेकर भोपाल निगम सेंट्रल वर्कशॉप में छापा

11 मार्च को अपर आयुक्त के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर

निगम में फर्जी भुगतान की शिकायत नवंबर 2025 में लोकायुक्त को मिली थी। प्रारंभिक जांच में तथ्य सही पाए जाने पर 11 मार्च को आयुक्त गुणवंत सेवतकर के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेकर छापेमारी की गई।

भोपाल (नप्र)। भोपाल नगर निगम में रविवार सुबह 9 बजे लोकायुक्त की टीम ने सेंट्रल वर्क शॉप माता मंदिर के करीब स्थित नगर निगम के ऑफिस में छापा मारा। टीम की छापा मार कार्रवाई अभी भी जारी है। दरअसल, बिना काम कराए फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए निकालने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के दौरान टीम को बड़े पैमाने पर सेंट्रल वर्कशॉप नगर निगम में वित्तीय अनीयमितताएं किए जाने के सबूत मिले थे। जिसके आधार पर रविवार को यह कार्रवाई की जा रही है। यहां निगम की गाड़ियों से जुड़े मैकेनिकल काम होते हैं।

निगम के डाटा सेंटर फतेहगढ़ से पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए करीब 10 साल के दस्तावेज और सर्वर डाटा जब्त कर लिया था। अब लोकायुक्त की टीम सेंट्रल वर्क शॉप स्थित ऑफिस से दस्ताजों की जांच कर रही है। साथ ही जिम्मेदार सहित वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है।

सॉफ्टवेयर से फर्जी बिल तैयार कराए- लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर के अनुसार, शिकायत में आरोप है कि सॉफ्टवेयर की मदद से फर्जी बिल तैयार कराए गए और बिना काम कराए ही परिचितों व रिश्तेदारों की फर्मों के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान कराया गया।

गड़बड़ीः बिना काम कराए ई-बिल से भुगतान- आरोप है कि नगर निगम के जलकार्य, सामान्य प्रशासन और केंद्रीय वर्कशॉप जैसे विभागों के नाम पर वाहनों की मरम्मत, पेंटिंग और अन्य काम दिखाए गए। कई मामलों में वास्तव में काम हुआ ही नहीं, लेकिन सिस्टम में ई-बिल तैयार कर दिए गए। कुछ मामलों में जिस विभाग के नाम से बिल बनाए गए, उन्हें ही इसकी जानकारी नहीं थी।

दो दिन पहले डेटा सेंटर से जब्त किए थे रिकार्ड- लोकायुक्त टीम ने शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे निगम के डाटा सेंटर फतेहगढ़ में छापेमारी की। लोकायुक्त का कहना है कि डिजिटल डाटा और दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में अन्य कर्मचारियों और फर्मों की भूमिका भी सामने आ सकती है। जब्त डेटा के एनालाइज केआधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

एसएपी सॉफ्टवेयर का डाटा जब्त किया- प्रारंभिक जांच में मोटर वर्क शाखा, जल कार्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े कुछ कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। जांच टीम ने भुगतान से जुड़े एसएपी सॉफ्टवेयर का डिजिटल डाटा भी कब्जे में लिया है। अब इसकी जांच कर यह पता लगाया जाएगा कि किन-किन कार्यों के नाम पर भुगतान किया गया और वास्तव में काम हुआ भी था या नहीं। अपर आयुक्त गुणवंत सेवतकर का कहना है कि लेखा शाखा में बिल सीधे तैयार या पास नहीं किए जाते। बिल संबंधित विभागों से सत्यापन के बाद आते हैं और फंड की उपलब्धता के अनुसार नगर निगम आयुक्त से चर्चा के बाद भुगतान किया जाता है।

दोस्त को वीडियो कॉल कर इंजीनियरिंग छात्र का सुसाइड

पिता बोले- रिश्तेदार ने सर्टिफिकेट दिलाने के नाम पर 1.30 लाख हड़पे, इसी से तनाव में था

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अशोका गार्डन में रहने वाले बी.टेक थर्ड ईयर के छात्र मोहम्मद इफ्तिखार ने शनिवार सुबह फांसी लगाकर सुसाइड किया था। लाइव सुसाइड उसने अपनी एक दोस्त को वीडियो कॉल पर दिखाया था। रविवार को परिजनों की मौजूदगी में बॉडी का पीएम कराया गया।

मृतक के पिता मोहम्मद नवाब अली ने आरोप लगाया कि उनके एक रिश्तेदार ने डिग्री दिलाने के नाम पर बेटे से 1.30 लाख रुपए ऐंठ लिए थे।

कई बार कहने पर भी रकम लौटाने को तैयार नहीं था। रकम मांगने पर बेटे को धमकाता था। इसी की प्रताड़ना के कारण बेटे ने जान दी है। हालांकि उन्होंने रिश्तेदार का नाम ऑन कैमरा नहीं बताया। इधर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल पर जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मूलरूप से पूर्वी चंपारण, बिहार निवासी मोहम्मद इफ्तिखार (21) यहां बैंक नगर कॉलोनी अशोका गार्डन में किराए से रह रहा था और रातीबड़ के निजी कॉलेज में बीटेक थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। इफ्तिखार अपने दोस्तों के साथ रहता था। बुधवार रात उसके दोस्त अपने अन्य दोस्तों के रूम पर थे जबकि इफ्तिखार रूम में अकेला था। रात करीब दो बजे तक वह अपनी फ्रेंड से बातचीत करता रहा और उसी दौरान

उसने फांसी लगा ली। रविवार को पिता सहित अन्य परिजनों की मौजूदगी में बॉडी का पीएम कराया गया।

छात्र की फ्रेंड के बयान से होगा खुलासा- रात करीब दो बजे फ्रेंड से बातचीत करते समय इफ्तिखार ने उससे आत्महत्या की बात कही थी। फ्रेंड ने इफ्तिखार के दोस्त को इस बात की जानकारी दी। दोस्त जब घर पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था। किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया। भीतर इफ्तिखार की लाश फंदे पर लटकी मिली। उसका मोबाइल दीवार से टिका हुआ था। पुलिस का अनुमान है कि फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान ही उसने फांसी लगाई है।

संपादकीय

यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का जोर

देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर जोर दिए जाने के बाद यह मुद्दा एक फिर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का समय आ गया है। इसमें संसद के लिए भी स्पष्ट संदेश है, लिहाजा यूसीसी लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार होना ही चाहिए। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि पर्सनल लॉ में व्याप्त विषमताओं और भेदभाव का सबसे प्रभावी समाधान यूसीसी ही है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद-44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत स्पष्ट कहा गया है कि राज्य पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिन्होंने महसूस किया कि धार्मिक आधार पर अलग-अलग कानून राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। पिछले कई दशकों में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले (1985), सरला मुद्गल (1995) और 2017 के तीन तलाक मामले (शायरा बानो) में यूसीसी की वकालत की है, लेकिन अब उसके रुख से यूसीसी के समर्थन वाला पक्ष और मजबूत ही हुआ है। दरअसल यूसीसी के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क महिलाओं के अधिकार का ही है। शरिया कानून में उत्तराधिकार, बहुविवाह इत्यादि मुद्दे लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं, जबकि यूसीसी इन आधारों पर होने वाली सभी किस्म की असमानताओं को खत्म कर एकसमान, निष्पक्ष और सांविधानिक मूल्यों पर आधारित ढांचा प्रदान कर सकता है। हालांकि कुछ समुदाय इसे संविधान के अनुच्छेद-25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला मानते हैं, जिस पर शीर्ष अदालत पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि यूसीसी का उद्देश्य धार्मिक प्रथाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों में समानता लाना है।

अदालत का यह कहना भी तर्कपूर्ण है कि शरिया कानून को एकदम से खत्म करने से एक अनावश्यक शून्य पैदा हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि विधायिका ही इस दिशा में धीरे-धीरे कदम बढ़ाए, जैसा उत्तराखंड ने किया, जो यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। उल्लेखनीय है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भाजपा के कोर एजेंडे में रहा है। वैसे गोवा में तो यह पहले से लागू है। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने पिछले साल 27 जनवरी को इसे लागू कर दिया था। उत्तराखंड में भाजपा ने यूसीसी को प्रायोगिक रूप से लागू किया था। इसका असर यह हुआ कि राज्य में विवाह पंजीकरणों की संख्या में भारी उछाल आया है। लिव इन रिलेशनशिप भी नियमों के दायरे में आ गई है। सभी धर्मों में महिलाओं को संपत्ति में समान हक और तलाक के नियम समान हो गए हैं। पहचान छिपाकर शादी करने पर भी कानून सख्त कर दिया गया है। साथ ही बहुविवाह, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर भी पूरी तरह रोक लग गई है। इसका सर्वाधिक लाभ मुस्लिम महिलाओं को ही मिला है। राज्य में यूसीसी का बड़े पैमाने पर विरोध भी अभी तक सामने नहीं आया है। यूसीसी का सर्वाधिक विरोध मुसलमानों द्वारा यह कहकर किया जाता रहा था कि यह उनके पर्सनल लॉ में सीधा दखल है। उत्तराखंड में मुस्लिम करीब 13 प्रतिशत हैं और ये मुख्य रूप से देहरादून, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में ही है। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मोदी सरकार इसे पूरे देश में लागू करने पर आगे बढ़ सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सरकार को नैतिक बल मिला है।

केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की घटती साख

नजरिया

रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी विचारक हैं।

27 फरवरी 26 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया आदि को ईडी के द्वारा दायर प्रकरण पर चार्ज लगाने के पूर्व ही मुक्त कर दिया। अदालत ने अपने लंबे आदेश में ईडी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की खामियों पर चर्चा की तथा उसने कहा कि ईडी के पास न तो प्रमाण हैं और न ही वह प्रमाणिक ढंग से आरोप सिद्ध कर सकी है। इस घटना ने फिर एक बार ईडी को कठघरे में खड़ा किया है। वैसे भी पिछले दिनों जो प्रकरण ईडी ने दायर किये और राजनैतिक नेताओं व लोगों को लंबे समय तक जेल में रखा, वे अधिकांश सिद्ध नहीं पाये गये। हालात इतने बदतर हैं कि ईडी के द्वारा बनाये गये प्रकरणों में मुश्किल से 3 प्रतिशत प्रकरणों में ही आरोपियों को दंडित किया जा सका है। वह भी छोटे-मोटे अधिकारी, कर्मचारियों को। राजनेताओं में तो शायद ही कोई ऐसा दुर्भाग्यशाली रहा हो जिसे ईडीध्सीबीआई की विशेष अदालत ने दंडित किया हो, कम से कम मेरी जानकारी में तो नही है। इसके पूर्व भी हेमंत सोरेने मुख्यमंत्री झारखंड, ए राजा (डीएमके) और ऐसे ही अनेक नाम लिये जा सकते हैं जिनमें कई-कई माह तक राजनेताओं को जेल में डाला गया, कई के राजनैतिक कैरियर नष्ट हो गये और उन्हें अनावश्यक सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में अपमानित व लज्जित होना पड़ा और अंत में ईडी/सीबीआई के मुकदमे खारिज हो गये।

हालांकि यह भी आश्चर्यजनक है कि इसी सीबीआई के जज श्री जितेन्द्र सिंह जिन्होंने अब यह फैसला दिया है, हालाँकि वे ही लगातार इन आरोपियों के जमानत आवेदनों को निरस्त भी करते रहे और ईडी को रिमांड देते रहे, जिससे इन आरोपियों श्री अरविन्द केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया या इसके पहले श्री संजय सिंह को इसी प्रकरण लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। होना तो यह चाहिए कि ऐसे गंभीर मामलों में यह कानून बने कि ईडी को या सीबीआई को व्यक्ति गिरफ्तार करते ही और कोर्ट में पेश करते ही चार्ज शीट पेश करने की अनिवार्यता हो। ताकि न्यायालय चार्ज लगाते समय प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रमाणिक निर्णय कर सके और इन ईडी या सीबीआई जैसे संस्थानों को रिमांड मांगने की जरूरत ही न पड़े। कोई भी व्यक्ति जो बाद में निरपराध सिद्ध हो, उसे अनावश्यक जेल में न रहना पड़े।

हालांकि ऐसे राजनैतिक आरोपों का चलन पहले भी रहा है। वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा नियंत्रित ईडी की कार्यवाही जो सिद्ध नहीं हुई जिसके कारण दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री को जेल में रहना पड़ा और इस्तीफा भी देना पड़ा था। बाद में चुनाव में उनकी सरकार भी चली गई। पूर्व में श्री अरविन्द केजरीवाल की संस्था इंडिया अगेंस्ट करप्शन्य की ओर से स्व. डा मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2जी स्पेक्ट्रम के घोटाले की बात कही गई थी उसमें 2 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में कई आईएएस अफसरों, मंत्री ए राजा और द्रमुक नेता स्व. करूणानिधि की बेटी सांसद श्री कनीमोझी को जेल में रहना पड़ा था और बाद में दोष भी सिद्ध नहीं हुआ। परंतु केन्द्र से स्व. मनमोहन की सरकार व दिल्ली से श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार चली गई और श्री अरविन्द केजरीवाल उससे लाभ उठाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तथा भाजपा ने उसका प्रचार कर बाद में दिल्ली में सरकार बनाई और श्री नरेन्द्र मोदी उसके प्रधानमंत्री बने। अगर उसके और पुराने इतिहास में जाएं तो स्वरू राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, स्वरू बी.पी. सिंह ने बोफोर्स घोटाले को उठाया व मुद्दा बनाया। बाद में राजीव गांधी की सरकार चली गई। स्वतः बी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने परंतु कोई घोटाला सिद्ध नहीं हुआ और सभी आरोपी बरी हो गये। यहाँ तक कि स्वरू अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में जब कारगिल में घुसपैठ हुई और इन घुसपैठियों को निकालने के लिये भारतीय सेना भेजी गई तो वही बोफोर्स तोपें कारगर साबित हुईं, और इनकी प्रशंसा हुई।

इन घटनाओं से दो निष्कर्ष निकलते हैं, एक-आजकल राजनेता और कारपोरेट मिलकर अपने प्रतिद्वंद्वी को बदनाम करने, गिराने और राजनैतिक लाभ के लिये झूठे प्रकरण उठाते हैं। इसमें दुनिया की बड़ी-बड़ी कारपोरेट कंपनियों का अंतर युद्ध प्रमुख भूमिका अदा करता है। जिस कंपनी को ठेका नहीं मिल पाता वह कंपनी 500-1000 करोड़ रुपया ऐसे झूठे अभियानों पर खर्च करती और सुनियोजित मुहिम चलाती है, सरकार को गिराती व बनाती है और फिर सरकार बदलने के बाद, अपनी लागत की वसूली करती है व मुनाफा कमाती है। देश की जनता मीडिया के प्रचार में वह जाती है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि राजनीति व राजनैतिक व्यक्तियों की साख आम जनता में इतनी गिर चुकी है कि उनके विरुद्ध लगाये गये प्रत्येक आरोप को देश सही मान लेता है। यह तो केवल गांधी ही है जिनके विरुद्ध लगभग 80 साल से देश की कुछ संस्थायें और पिछले 11-12 वर्षों से सरकार के संरक्षण में कानाफूसी, सोशल मीडिया, अखबारी बयान और हर प्रकार से झूठ व निंदा का अभियान चलाया जा रहा है, परंतु गांधी का सम्मान और सत्य शास्वत है। भारतीय राजनीति व नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी साख इतनी गिरी हुई और कमजोर क्यों है? अब यह सिद्ध हो चुका है और जनमानस में स्वीकार तथ्य हो चुका है कि ईडी/सीबीआई जैसी संस्थायें जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने तोता कहा था वस्तुतरू तोता ही है। वह तत्कालीन सरकार के अपने मालिकों की भाषा बोलते हैं। कटु सत्य तो यह है कि ईडी और सीबीआई की विश्वसनीयता आम जनमानस में समाप्त हो चुकी है। वह जिनके विरूद्ध कार्यवाही करते हैं उस पर सामान्य प्रतिक्रिया होती है तथा आम जनमानस में यह धारणा बनती है कि फँसाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की साख व प्रमाणिकता इतनी गिर चुकी है कि अब उनके किसी भी कार्यवाही को आम जन सत्ता के द्वारा की गई कार्यवाही ही मानता है। यहाँ तक कि अगर वह कोई सच कार्यवाही भी करेंगे तो भी वह आम जनमानस में झूठी मानी जायेगी। न्यायपालिका में अपने अभियोजन को सिद्ध करने की उनकी दर भी लगभग नगण्य है, याने मात्र 3 प्रतिशत। यहां तक की पुलिस जो बदनाम संस्था है,उसके अभियोजन की सफलता दर ईडी/सीबीआई से कई गुना अधिक है। अब यह भावना देश में बन रही है कि ईडी/सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की उपयोगिता शून्य हो चुकी है और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।

चौथा प्रश्न आम जनमानस में है कि जब न्यायपालिका ईडी, सीबीआई पुलिस की कार्यवाही को न केवल गलत ठहराती है बल्कि उनकी विवेचना और अभियोजन में गंभीर त्रुटियां इंगित करती है जिससे आरोपित अपराधी निर्दोष बरी होते हैं, तो न्यायपालिका इन जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध झूठे अभियोजन और पीड़ित पक्षकारों को क्षतिपूर्ति के लिये आदेश क्यों नहीं करती? ऐसे गैर जिम्मेवार और सत्ता निष्ठा वाले अधिकारियों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए जिन्होंने न केवल झूठे प्रकरण बनाये या किसी को बचाने के लिये दबाने का अपराध किया है।

यह समाचार पत्रों में समाचार आये है कि ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में श्री अरविन्द केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया की चार्ज फ्रेम के पूर्व रिहाई के विरुद्ध अपील करने की तैयारी में है। संभव है कि अपनी साख बचाने के लिये वह अपील करे और एक रूटीन प्रक्रिया में उच्च न्यायालय स्थगन दे दें तथा ईडी/सीबीआई को अपनी फौरी साख बचाने और अपराध के लिये छिपाने के लिये अवसर मिल जाये।

1990 में हवाला कांड हुआ था जिसमें दानदाताओं ने एक साथ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, जेकेएलएफ के मुखिया श्री अमानउल्ला खान, और अन्य अनेक सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों को पैसे दिए थे और उन सभी पर आरोप लगे थे। यहां तक कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश स्वरू जे एस वर्मा के बड़े-बड़े बयान अखबारों व पत्रिकाओं में उन दिनों छपते थे जिनमें कहा जाता था कि मैं स्वतः इसका निरीक्षण करूंगा, उनकी निगरानी में जांच व कार्यवाही होगी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि इस कांड के आरोपों से मुझे रात में नींद नहीं आती और अनेक लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए। यह प्रकरण जिस डायरी की सूची के आधार पर दर्ज हुए थे हमारे देश की महान जांच एजेंसी सीबीआई उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई और जिस प्रकरण की जांच की निगरानी भारत के मुख्य न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से कर रहे थे उस प्रकरण को एक जिला स्तर के जज ने यह लिखकर समाप्त कर दिया कि अकेले डायरी कोई साक्ष्य नहीं होती जब तक कि कोई अन्य उसकी पुष्टि न करे। याने भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च अदालत को इस नजीर का पता नहीं था कि अकेले डायरी प्रमाण नहीं मानी जाती। कुल मिलाकर देश की सरकारें, जांच एजेंसियां और कुछ हद तक न्यायपालिका भी आम जनमानस में विश्वासनीयता खो चुकी है, यह गंभीर चिंता का विषय है।

मैं समझता हूँ कि अब भारत सरकार को

1. सीबीआई/ईडी जैसी जांच एजेंसियों को या तो समाप्त कर देना चाहिए या उन्हें निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाने के लिये चयन प्रक्रिया और काम की आजादी के प्रावधान करना चाहिये।

2. जहां भी न्यायपालिका अपने निर्णय में पुलिस या जांच एजेंसियों को आरोपित करती है वहां संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पीड़ित पक्ष का उनके वेतन राशि या जमा निधि से हर्जाना दिलाने का कानून बनना चाहिए, और आरोपकर्ताओं को राजनैतिक अधिकारों से डिसक्वालिफाई किया जाना चाहिए।

एक जनचर्चा यह भी है कि ईडी अदालत के इस निर्णय के पीछे चुनावी राजनीति है। मैं इसके बारे में आज प्रमाणिक तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, परंतु यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर विचार होना चाहिए।

न्यायालय ने दी सम्मान से मृत्यु की अनुमति

इच्छा मृत्यु

प्रमोद भार्गव
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

निष्क्रिय इच्छा-मृत्यु को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में 12 साल से कोमा में रहते हुए कृत्रिम जीवन रक्षा उपायों से जीवित 32 वर्ष के हरीश राणा को मौत की अनुमति दे दी। देश के इतिहास में इच्छा मृत्यु की यह पहली कानूनी इजाजत है। अब हरीश के जीवन रक्षक उपकरण हटा लिए जाएंगे और उसकी जीवन-लीला प्राकृतिक रूप से मौत को प्राप्त हो जाएगी। न्यायालय की न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने परोक्ष इच्छा-मृत्यु की इजाजत मांगने वाली याचिका की स्वीकार करते हुए एम्स दिल्ली को निर्देश दिया है कि 'वह तय करे कि जीवन रक्षक उपकरण और प्रणाली एक सुनियोजित ढंग से हटाई जाए,ताकि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे तथा उसे कोई पीड़ा झेलनी न पड़े। वैसे भी उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, यह स्थिति सिर्फ दुख दे रही है।' हरीश पंजाब विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के छात्र रहने के दौरान 2013 में पेइंग गेस्ट आवास की चौथी मंजिल से गिर गए थे।तब से वे कोमा में हैं। उनके पिता अशोक राणा ने उक्त याचिका अदालत में दाखिल की थी।

2018 में कॉमन काज की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायमूर्तियों की पीठ ने परोक्ष इच्छा-मृत्यु (पैसिव इथुनीशिया)को मान्यता से जुड़ा फैसला दिया था। न्यायालय ने कहा था कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और लिविंग विल (इच्छा-पत्र) बना चुके हैं, उनको सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। उन्हें कानूनी पेंच में नहीं फंसाना चाहिए और चिकित्सा विशेषज्ञ को भी ऐसे मामले संज्ञान में लेना चाहिए। अतएव न्यायालय का निष्कर्ष था कि अगर कोई व्यक्ति अपना उपचार बंद कराना चाहता है तो उसे अनुमति देने का भी नियम होना चाहिए। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस निर्णय में मृत्यु के अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना है। लिविंग विल के मायने जीवित होने का दस्तावेज या वसीयत है। इसके जरिए मरणासन्न व्यक्ति या उसके परिजन अपनी इच्छा के जरिए इच्छा-मृत्यु की मांग कर सकते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति की राय पर इच्छा मृत्यु की पहल की जा सकती है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ही यह पहली अनुमति अदालत ने दी है।

इच्छामृत्यु की हमें पहली जानकारी भीष्म पितामह द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार मौत का वरण करने की मिलती है। जैन धर्म में ऋषि-मुनी संथरा के जरिए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करते हैं। जब कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी या दुर्घटना के चलते ऐसी नीम-बेहोशी की हालत में आ जाए कि उसकी स्मृति का लोप होने के साथ खाने-पीने व दिनचर्याओं से निवृति की शक्ति का क्षरण हो जाए और वह अपने अस्तित्व का बोध भी न कर पाए तो ऐसे दुर्लभ कष्ट से मुक्ति के लिए मौत जरूरी लगने लगती है। ऐसी हालात में रोगी को जीवन रक्षक प्रणाली पर टिकाए रखना उसे यातना देने की तरह है। उसके इस कष्टदायी जीवन से परिजन और शुभचिंतक भी अप्रत्यक्ष रूप से यातना ही भोगते है। परिजनों को आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। हरीश के पिता अशोक की पुत्र की इस लाइलाज बीमारी से दिल्ली का घर बिक गया। पिता जीवन-यापन के लिए क्रिकेट मैदानों में सैंडविच बेचकर गुजारा करने को मजबूर थे।

भारत में यह मुद्दा तब देशभर में विचार व बहस का विषय बना था, जब मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग की दया मृत्यु के लिए शीर्ष न्यायालय में गुहार लगाई गई थी। बलात्कार और हत्या की निर्मम दुष्टता के चलते कोमा में पहुंची अरुणा ने 42 साल तक जीवन रक्षक प्रणाली पर टिके रहने की यातना भोगी। अरुणा को सामान्य अवस्था में लाने की जब सभी चिकित्सा कोशिशें व्यर्थ हो गई, तब अदालत में उन्हें इच्छा मृत्यु देने की याचिका लगाई गई थी। किंतु अदालत ने इसे उचित नहीं ठहराया था। 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में इस आशय की अर्जी भी लगाई थी की अरुणा का इलाज संभव नहीं है, लिहाजा उसे जीवन रक्षक प्रणाली से मुक्त करने की इजाजत दी जाए। जिससे उसे, अंतहीन कष्टों से छुटकारा मिले। लेकिन इच्छा-मृत्यु वैध है या अवैध इसके अंतिम निष्कर्ष पर अदालत नहीं पहुंच पाई थी। लिहाजा उसने निष्क्रिय अवस्था में पड़े व्यक्ति की जीवन रक्षा प्रणाली हटाकर उसे मौत का वरण करने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता देने का सवाल उठाते हुए सभी राज्य व केंद्र शासित प्रांतों को नोटिस जारी करके सलाह मांगी। तब के प्रधान न्यायमूर्ती आरएस लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय खंडपीठ ने इच्छा-मृत्यु पर विचार आमंत्रित करने के पक्ष में तर्क दिया था कि यह मसला संविधान ही नहीं बल्कि नैतिकता, धर्म और चिकित्सा विज्ञान से भी जुड़ा है, इसिलए इसे विचारना जरूरी है। इसके उलट केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार कहती रही कि यह एक तरह की अत्महत्या है, जिसकी अनुमति भारत में नहीं दी जा सकती, क्योंकि इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी गई तो इसका दुरुपयोग हो सकता है?

इसके जवाब में संविधान पीठ का तर्क था कि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय होने चाहिए। लिहाजा अदालत ने याचिकाकर्ता पिंकी से जानना चाहा था कि 'जीवन का अंत करने के लिए सबसे कम पीड़ादायी तरीका कौन सा हो सकता है? क्योंकि दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है, किंतु इस परिप्रेक्ष्य में किसी अंतिम निष्कर्ष पर आम राय नहीं बन सकी है। गोया, अदालत ने कहा था कि 'कानून का दुरुपयोग इच्छा मृत्यु को कानूनी दर्जा नहीं देने का आधार नहीं हो सकता है। विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता के विचार का विरोध किया था। अरुणा से जूड़ी याचिका पर ही सुनवाई करते हुए तबके न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू की अध्यक्षता वाली पीठ ने इच्छा-मृत्यु को गैरकानूनी करार देते हुए निरस्त कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में दलील दी थी कि असामान्य परिस्थितियों में निष्क्रिय व्यक्ति को इच्छा-मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जब तक संसद इस बारे में कोई कानून नहीं बनाती, तब तक निष्क्रियऔर सक्रिय दोनों प्रकार की इच्छा-मृत्यु को अवैधानिक ही माना जाएगा। धर्म, संस्कृति, परंपरा, दर्शन और नैतिकता से जुड़ा यह मुद्दा निसंदेह जटिल था, इसलिए इस पर एक राय बनना कठिन थी। संविधान का अनुच्छेद-21 जीवन को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन उसमें गरिमापूर्ण मृत्यु के वरण का अधिकार शामिल नहीं है। इच्छा-मृत्यु के विवाद को अंतिम निराकरण तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में जीवन रक्षा की ऐसी प्रणालियां विकसित हो चुकी हैं, जो जीवन और मृत्यु की कड़ी को अर्से तक उलझाए रखती हैं। चिकित्सा में निजीकरण ऐसे उपायों को और बढ़ावा दे रहा है। देश में यातायात से जुड़ी दुर्घटनाओं में ऐसे घयालों की संख्या लगातार बढ़ रही है,जो दशकों से कोमा में हैं। केवल जीवन रक्षा प्रणाली के जरिए एक हद तक उनमें प्राणवायु का संचार बना रहता है। मूर्छित अवस्था वाले ऐसे रोगियों के उपचार से परिजन या तो कंगाल हो रहे हैं या फिर मरीजों को अस्पताल में ही छोड़ देने की बेरहमी दिखाने को विवश हो रहे हैं, क्योंकि उपचार की ऐसी दीर्घ अवधि में उन्हें आजीविका के संसाधनों को नियमित बनाए रखने में भी अनेक कठिनईयों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल दुनिया में अब तक स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है, जहां कुछ शर्तें पूरी कर लेने के बाद इच्छा-मृत्यु की अनुमति दे दी जाती है। अब भारत भी इस कड़ी में का हिस्सा बन गया है।

शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से विकसित होती हुई एक महान संस्कृति और जीवन-दृष्टि का प्रतीक है। यहाँ की परंपरा में शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं माना गया, बल्कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण, नैतिक विकास और सामाजिक जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया है। भारतीय शिक्षा का मूल उद्देश्य ऐसे मनुष्य का निर्माण करना रहा है जो ज्ञानवान होने के साथ-साथ संवेदनशील, कर्तव्यनिष्ठ और संस्कारित भी हो। इसी कारण आज के समय में शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश अत्यंत आवश्यक हो गया है।

भारतीय संस्कृति की जड़ें सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सम्मान, परोपकार और कर्तव्यनिष्ठा जैसे उच्च आदर्शों में निहित हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ, महापुरुषों के जीवन प्रसंग और गुरुकुल परंपरा इस बात का प्रमाण हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी था। उस समय गुरु विद्यार्थियों को केवल विषयों का ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से उन्हें जीवन के श्रेष्ठ मूल्यों से भी परिचित कराते थे। इसलिए उस शिक्षा का प्रभाव केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि विद्यार्थियों के पूरे जीवन को दिशा प्रदान करता था।

आज का युग विज्ञान, तकनीक और प्रतिस्पर्धा का युग है। शिक्षा के क्षेत्र में भी तीव्र परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आधुनिक शिक्षा ने ज्ञान और अवसरों के नए द्वार अवश्य खोले हैं, किंतु कई बार यह भी देखा जाता है कि विद्यार्थी ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनमें संवेदनशीलता, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अभाव रह जाता है। जब शिक्षा केवल अंकों, परीक्षाओं और करियर तक सीमित हो जाती है, तब उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। ऐसे समय में शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश एक संतुलित और मानवीय समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक बन जाता है।

शिक्षा में भारतीय मूल्यों को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम पाठ्यक्रम हो सकता है। विद्यालयों में ऐसे साहित्य, कथाएँ और प्रेरक प्रसंगों को स्थान दिया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों में सत्यनिष्ठा, साहस, त्याग और सेवा की भावना को जागृत करें। भारत के महान व्यक्तित्वों के जीवन से जुड़े प्रसंग विद्यार्थियों को यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आदर्शों और नैतिकता से भी मापी जाती है। ऐसे प्रेरक उदाहरण बच्चों के मन में सकारात्मक विचारों और श्रेष्ठ आचरण की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं।

शिक्षा में मूल्यों के समावेश में शिक्षक की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा और आदर्श होते हैं। यदि शिक्षक अपने व्यवहार में ईमानदारी, अनुशासन, सहानुभूति और सम्मान जैसे गुणों का पालन करते हैं, तो विद्यार्थी भी उन्हें सहज रूप से अपनाने लगते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व और उसका आचरण विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव डालता है, इसलिए मूल्य आधारित शिक्षा के लिए शिक्षक का संवेदनशील और आदर्शवादी होना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विभिन्न सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भी भारतीय मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। जैसे– सामूहिक कार्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और जरूरतमंदों की सहायता जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में सहयोग, संवेदना और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। ऐसी गतिविधियाँ विद्यार्थियों को यह समझने में सहायता करती हैं कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत सफलता का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के कल्याण का मार्ग भी है।

भारतीय मूल्य हमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना सिखाते हैं, जिसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। यदि यह भावना विद्यार्थियों के भीतर विकसित हो जाए, तो वे संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर मानवता और वैश्विक भाईचारे की दिशा में सोचने लगते हैं। आज के समय में जब समाज में कई प्रकार की असहिष्णुता और विभाजन देखने को मिलता है, तब शिक्षा के माध्यम से इस व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश केवल विद्यालय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि परिवार और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब घर और विद्यालय दोनों स्थानों पर समान मूल्यों को महत्व दिया जाता है, तब बच्चे उन्हें सहज रूप से अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। माता-पिता, शिक्षक और समाज यदि मिलकर बच्चों को सही दिशा प्रदान करें, तो उनका व्यक्तित्व संतुलित, संवेदनशील और सशक्त बन सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि समय की अनिवार्य आवश्यकता है। ज्ञान और तकनीक के साथ-साथ यदि शिक्षा संस्कार और नैतिकता भी प्रदान करे, तभी वह पूर्ण मानी जाएगी। भारतीय मूल्यों से समृद्ध शिक्षा ही ऐसे नागरिकों का निर्माण कर सकती है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों की धारा भी निरंतर प्रवाहित होती रहे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सिलेंडर के मारे शादी वाले दुखियारे

व्यंग्य

डॉ. महेन्द्र अग्रवाल
लेखक व्यंग्यकार हैं।

ईरान-इज़राइल जैसा युद्ध इस समय राम प्रसाद जी के दिलो दिमाग में चल रहा था। रह रहकर सायरन सा बज उठता। रह रहकर लगता कहीं कोई मिसाइल गिर गई है। वह सोचते सोचते कम्पित धरती से कांप कर रह जाते। हालांकि वह न ईरान में रह रहे थे और न इज़राइल में, न किसी अन्य खाड़ी देश में,पर लग ऐसा रहा था जैसे वहीं के निवासी हां और उन पर कोई आपदा टूट पड़ी हो। आपदा भी ऐसी वैसी नहीं जिसमें कोई अवसर हाथ लग जाए,यह तो सौ फीसदी आपदा थी जिसमें वह बुरी तरह उलझ कर रह गये थे।

दरअसल उनके बेटे की शादी थी। निमंत्रण पत्र पन्द्रह दिन पहले बंट चुके थे। कुछ मेहमान घर में आ गए थे और कुछ होटलों में आने वाले थे। घर में पहली शादी होने से दो हजार लोगों के भोज की व्यवस्था थी। होटल,मैरिज गार्डन, बैंड बाजे सब बुक थे ।कहीं कोई परेशानी नहीं। हल्वाई भी अपने चालीस चेलों की टीम के साथ अपना हुनर दिखाने को मुस्तैद खड़ा था। बर्तन भगोने भी किचन टीन शेड में बिखर गये थे। गैस भट्टियां भी करीने से जलने के इंतजार में लाइन लगाये थीं। पर,नहीं थे केवल सिलेंडर।

जबसे शासन का आदेश आया कि शादी विवाह या व्यवसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं होगा,केवल कमर्शियल सिलेंडर ही प्रयोग होंगे स्थिति बदल गई। कानून के चाबुक के डर से महंगा होने के बाद भी कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होने लगा। किंतु युद्ध के कारण कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक खत्म हो गया। होटल,रेस्टोरेंट या गली मुहल्ले के छोटे-मोटे हल्वाई सभी तीन दिन से काम धंधा बंद कर घर बैठ गये। ामप्रसाद जी ने गैस एजेंसी वाले को फोन लगाया तो उसने परिचित होने के नाते तीन दिन पहले भी कह दिया था कि आप बिल्कुल परेशान न हां सिलेंडर आ जाएंगे नहीं तो आपको डॉमेस्टिक सिलेंडर दे दूंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी और फूड वालों को भी कह दूंगा कि आपको परेशान न करें।

एक दिन पहले भी राम प्रसाद जी ने हल्वाई से बात कर उनसे पैंतालीस सिलेंडर की बुकिंग का बोल दिया था और उसने भी डेढ़ सौ रुपए प्रति सिलेंडर एबव में डन कर दिया। आज सुबह डिलीवरी होनी थी। कल की शादी थी पर हलवाई को अपनी टीम के साथ आज से काम शुरू करना था। उन्होंने एजेंसी वाले को फोन लगाया तो उसने सीधे हाथ खड़े कर दिये। बोला- मैं क्या करूं बाबूजी, तीन दिन से एक भी गाड़ी नहीं आई। गोदाम में भी एक भी सिलेंडर नहीं है। मेरे घर के दो सिलेंडर हैं ज्यादा से ज्यादा वही दे सकता हूं। वह भी आप घर के हो इसलिए,और क्या करूं? एक बार तो लगा जैसे इसमें भी एहसान कर रहा है। अब रामप्रसाद जी भी क्या बताएं? अपरिचित होता तो चिल्ला चांट कर लेते। एक दो गाली सुनाकर मन हल्का कर लेते। पर अब क्या करें? दो हजार लोगों के खाने में दो सिलेंडर से क्या होगा? चालीस आदमी लिए हलवाई सिर पर खड़ा है। एक बारगी तो उन्हें भी यही लगा कि युद्ध यहीं मैरिज गार्डन के मैदान में हो रहा है। बार-बार कान में धमाके गूंज रहे थे। किसी मिलने वाले की आवाज कान में आती तो लगता जैसे कोई मिसाइल फट गई है। फिर किसी शुभचिंतक ने समझाया कि साले से दो सिलेंडर ही मंगवा लो। न खाली वापस करना न पैसे देना। एक दो आपके घर में भी होंगे,उठवा लो। शहर में जितने रिश्ते नातेदार हैं उनको फोन लगाकर कह दो कि अभी खाना खाने आएं तो अपने घर से एक दो सिलेंडर अपने वाहन पर रखकर ले आएं। सबके नाम नोट कर बाद में वापस कर देना,हल्वाई का काम तो शुरू हो जाएगा। शाम तक और व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। शहर में जो लोग थोक में ऑन एबव सिलेंडर देने का बिजनेस करते हैं वह डेढ़ सौ की जगह तीन सौ लेंगे,काम तो चलेगा। और आप भी मिठाई सब्जी आधी कर दो क्योंकि अब नोते बांटने के बाद आदमी तो आधे नहीं हो सकते।

राम प्रसाद जी को जैसे मिर्गी के दौरे के बाद थोड़ा सा होश आया।उन्होंने प्राप्त प्रवचन को अमली जामा पहनाना शुरू किया। इसी होंचपोंच में एक परम शुभचिंतक और टपक पड़े। उन्होंने संकटमोचन की भूमिका निभाते हुए ज्ञान बघारा-राम प्रसाद जी आप तो सब छोड़ो। बफे की जगह पत्तल सिस्टम पर उतर आओ। केवल तीन सब्जी और चार मिठाई बनवा लो। ज्यादा हो तो वर वधु पक्ष के बैनर के साथ एक बैनर और लगा देना कि युद्ध के कारण सिलेंडर उपलब्ध न होने से मीनू चौथाई रह गया है।

गांधी का सर्व धर्म आज सर्वाधिक प्रासंगिक

दृष्टिकोण

अरुण कुमार डनायक

लेखक गांधी विचारों के अध्येता हैं।

सर्वसम्मति बन जाने के कारण भारत ने प्रस्ताव का प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, पर 'व्याख्या-स्थिति' दर्ज कराते हुए बहुलवाद को केंद्र में रखने की आवश्यकता पर बल दिया और 16 नवंबर के अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का उल्लेख करते हुए सभी प्रकार के धार्मिक पूर्वाग्रहों को समग्र रूप से संबोधित करने की बात कही। इसी क्रम में 2024 में प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव से, जो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा, और कुरान की अवमानना की निंदा करता है, भारत ने मतदान प्रक्रिया से स्वयं को प्रथक कर लिया। पुर्तगाल सहित कुछ यूरोपीय देशों एवं भारत, का मत है कि यह प्रस्ताव एक धर्म विशेष पर केंद्रित है, जबकि सभी धर्मों के विरुद्ध असहिष्णुता को समान रूप से संबोधित किया जाना चाहिए; इसलिए वे इसे औपचारिक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपनाते हैं और आयोजन प्रायः नागरिक संगठनों या स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित रहते हैं।

इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 15 मार्च को 'इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' मनाया जाता है। यह तिथि 2019 में न्यूज़ीलैंड के क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हुए आतंकी हमलों में 51 मृतकों की स्मृति से जुड़ी है, जिसने धार्मिक घृणा के हिंसक परिणामों को वैश्विक स्तर पर उजागर किया। इसी पृष्ठभूमि में पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन के समर्थन से प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसे धार्मिक सहिष्णुता, भेदभाव-निरोध व मानवाधिकारों जैसी व्यापक कूटनीतिक शब्दावली में प्रस्तुत कर वैश्विक सहमति बनाई, जिसके परिणामस्वरूप वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम सहमति से पारित हो सका।

सर्वसम्मति बन जाने के कारण भारत ने प्रस्ताव का प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया, पर 'व्याख्या-स्थिति' दर्ज कराते हुए बहुलवाद को केंद्र में रखने की आवश्यकता पर बल दिया और 16 नवंबर के अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस का उल्लेख करते हुए सभी प्रकार के धार्मिक पूर्वाग्रहों को समग्र रूप से संबोधित करने की बात कही। इसी क्रम में 2024 में प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव से, जो मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, हिंसा, और कुरान की अवमानना की निंदा करता है, भारत ने मतदान प्रक्रिया से स्वयं को प्रथक कर लिया । पुर्तगाल सहित कुछ यूरोपीय देशों एवं भारत, का मत है कि यह प्रस्ताव एक धर्म विशेष पर केंद्रित है, जबकि सभी धर्मों के विरुद्ध असहिष्णुता को समान रूप से संबोधित किया जाना चाहिए; इसलिए वे इसे औपचारिक राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अपनाते हैं और आयोजन प्रायः नागरिक संगठनों या स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने हाल के वर्षों में इस्लामोफोबिया की बढ़ती घटनाओं को 'महामारी जैसी स्थिति' बताया है। यूरोप, अमेरिका और कनाडा में सर्वेक्षणों व आधिकारिक आंकड़ों से मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह और घृणा अपराधों में वृद्धि के संकेत मिले हैं। भारत में, जहाँ मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हैं, कुछ स्वतंत्र अध्ययनों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि ध्रुवीकरण और घृणा-भाषण सामाजिक तनाव को बढ़ा रहे हैं। इन रुझानों से स्पष्ट है कि यह समस्या केवल पूर्वाग्रह तक सीमित नहीं, बल्कि हिंसा, धार्मिक स्थलों पर हमलों और सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार के रूप में भी प्रकट हो रही है।

इस्लामोफोबिया की जड़ें यरूशलम के क्रूसेड्स, स्पेन के रिकॉनक्विस्टा तथा भारत में मंदिर-मस्जिद विवाद जैसे मध्ययुगीन धार्मिक संघर्षों, औपनिवेशिक मानसिकता और उस प्रवृत्ति में निहित हैं, जिसमें भिन्न धार्मिक या सांस्कृतिक समुदायों को 'पराया' या 'खतरे' के रूप में चित्रित किया गया। आलोचक कुरान की कुछ युद्ध-संदर्भित आयतों का हवाला देकर इसे गैर-मुस्लिमों के विरुद्ध हिंसा से जोड़ते हैं, किंतु इन आयतों का संदर्भ 7वीं शताब्दी के विशिष्ट संघर्षों और आत्मरक्षा की परिस्थितियों से जुड़ा है। साथ ही कुरान न्याय, सहअस्तित्व और सीमा-नियंत्रण पर बल देता है। अतः चयनित पंक्तियों के आधार पर समग्र धर्म को हिंसक सिद्ध करना न तो ऐतिहासिक रूप से उचित है और न ही बौद्धिक रूप से न्यायसंगत। दूसरी ओर, अल-कायदा, आईएसआईएस, तालिबान, हिजबुल्लाह और हमास जैसे इस्लामी उग्रवादी समूह हिंसा का सहारा लेते रहे हैं, यद्यपि वे मुख्यधारा इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 9/11 जैसे हमलों के बाद मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने की प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर बढ़ी, जिससे इस्लामोफोबिया को बल मिला। भारत में 1993 के मुंबई धमाके, 2001 का संसद हमला और कश्मीर की हिंसा, तथा हालिया इज़राइल-हमास/ हिजबुल्लाह संघर्ष जैसे घटनाक्रमों ने इस धारणा को और तीव्र किया। फिर भी, आतंकवाद के सबसे अधिक शिकार स्वयं मुसलमान भी रहे हैं, और अनेक मुस्लिम संगठनों व राष्ट्राध्यक्षों ने इसकी स्पष्ट निंदा की है।

इस्लामोफोबिया का प्रसार केवल धार्मिक पूर्वाग्रह का परिणाम नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों से जुड़ा है। आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी और संकट के दौर में अल्पसंख्यकों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मुस्लिम समुदाय के प्रति नकारात्मकता गहराती है। राष्ट्रवादी राजनीति भी कई बार बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देकर उन्हें 'सांस्कृतिक' या 'सुरक्षा' खतरे के रूप में प्रस्तुत करती है। सोशल मीडिया की भ्रामक और मीडिया की सनसनीखेज प्रस्तुति इस धारणा को और मजबूत करती है। कुल मिलाकर, यह एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिघटना है, जो आर्थिक असंतुलन, राजनीतिक विमर्श और सूचना-परिस्थिति से प्रभावित होती है।

इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षा, जागरूकता और नीतिगत सुधार आवश्यक हैं, ताकि पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर समावेशी समाज को बढ़ावा मिल सके। संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों से धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा का आग्रह किया है। इसके लिए प्रभावी घृणा-अपराध कानून, संवेदनशील पुलिस-न्याय तंत्र तथा आभासी माध्यमों पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। साथ ही मुस्लिम समुदाय को भी मध्ययुगीन कठमुल्लापन, रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास त्यागकर सामाजिक सहभागिता, आधुनिक न्याय मूल्यों तथा अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता अपनानी चाहिए। खासतौर पर मदरसा शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक विज्ञान, संवैधानिक मूल्यों और अंतरधार्मिक समझ से जोड़ना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। आज जब विश्व धार्मिक पहचान के आधार पर विभाजनों से जूझ रहा है, महात्मा गांधी का सर्वधर्म समभाव अत्यंत प्रासंगिक है। उनकी दैनिक प्रार्थना में सभी धर्मों की स्तुतियों का समावेश था। वे मानते थे कि इस्लाम का प्रसार तलवार से नहीं, बल्कि पैगंबर मुहम्मद के नैतिक गुण, न्यायप्रियता और आध्यात्मिक शक्ति से हुआ। वे भारत के मुसलमानों में दिखाई देने वाली असहिष्णु व हिंसक प्रवृत्तियों को हजरत उमर की सहिष्णुता और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत मानते थे। गांधीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय में पाई जाने वाली असहिष्णुता, कट्टरता या हिंसा उस धर्म की मूल शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मुस्लिम इतिहास में सूफियों और फकीरों की आध्यात्मिक शक्ति ने धर्म की स्थायित्वता सुनिश्चित की, न कि हिंसा। गांधीजी का यह दृष्टिकोण आज इस्लामोफोबिया को चुनौती देने और सभी धर्मों के मूल उद्देश्य–मानव कल्याण–को समझने में सहायक है।

इस्लामोफोबिया से निपटने का अंतरराष्ट्रीय दिवस सिर्फ औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और सामाजिक जागरूकता का अवसर है। यह हमें सोचने को विवश करता है कि हम विविधता को भय की दृष्टि से देखते हैं या समृद्धि और सह-अस्तित्व का अवसर मानते हैं। वास्तविकता यह है कि धर्म, जाति, रंग, भाषा और नस्ल के आधार पर भेदभाव आज भी विश्वभर में व्याप्त है–अमेरिका में नस्लवाद, भारत में जातिगत असमानताएँ और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव इसके जीवंत उदाहरण हैं। इसलिए ऐसे दिवस की सार्थकता तभी है जब वे किसी एक धर्म तक सीमित न रहकर समग्र समावेशिता, समानता और मानवाधिकार की सार्वभौमिक प्रतिबद्धता को प्रेरित करें। महात्मा गांधी का संदेश याद दिलाता है कि सहिष्णुता कानून से नहीं, हृदय की उदारता से आती है। भारत जैसे बहुधार्मिक देश इस दिशा में वैश्विक नेतृत्व कर सकते हैं ।

हॉर्मुज जैसे संकरे जलमार्ग सुरक्षित रहना जरूरी

वैश्विक चिंता

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

विश्व के महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य (Straits) संकरे समुद्री मार्गों में से मलक्का, हॉर्मुज, बाब-अल-मंडेब और जिब्राल्टर सबसे प्रमुख हैं। ये वैश्विक तेल और वस्तु व्यापार (लगभग 25% मलक्का से) को नियंत्रित करते हैं और समुद्री यात्रा का समय कम करते हैं। भारत के लिए अन्य वैकल्पिक समुद्री मार्गों की बात करें तो मलक्का जलडमरूमध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है, जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 25% अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है। सुएज नहर जलमार्ग मिस्र में स्थित है, जो भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, खासकर यूरोप और मध्य पूर्व के साथ व्यापार के लिए। केप ऑफ गुड होप जलमार्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है।

विश्व में कई महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य (Straits) हैं, जो न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। जलडमरूमध्य पानी का वह संकरा मार्ग होता है जो दो बड़े जल निकायों (जैसे समुद्र या महासागर) को जोड़ता है और दो भू-भागों को अलग करता है। जलडमरूमध्यों का विश्व की अर्थ व्यवस्था, यातायात, माल परिवहन, ऊर्जा सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है। ये मार्ग वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए 'शॉर्टकट' का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, मलक्का जलसंधि के बिना जहाजों को हजारों मील का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ेगा। हॉर्मुज जैसे जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20-30 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है। इनका बंद होना वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल ला सकता है। युद्ध की स्थिति में इन संकरे रास्तों पर नियंत्रण रखने वाला देश दुश्मन की आपूर्ति लाइन को काट सकता है। इन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के 'गले' की तरह देखा जाता है; यहाँ छोटी सी रुकावट भी पूरी दुनिया में मंदी ला सकती है।

इन दिनों ऐसा ही एक जलडमरूमध्य (Straits) हॉर्मुज जलडमरूमध्य वर्तमान में एक बड़े भू-राजनीतिक तनाव के संदर्भ में बहुत चर्चित हुआ है। मार्च 2026 की खबरों के अनुसार, ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने इस मार्ग को असुरक्षित बना दिया है। ईरान ने स्पष्ट किया कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी नौसेना के साथ समन्वय (coordination) करना होगा। ईरान ने अमेरिका और इजरायल समर्थित जहाजों को रोकने या उन पर कड़ी निगरानी रखने की चेतावनी दी है। इसके जवाब में अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। भारत के लिए भी यह मार्ग अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि भारत का अधिकांश तेल आयात यहीं से होता है। हाल ही में भारत सरकार और ईरान के बीच बातचीत हुई है ताकि वहां फंसे भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित निकाला जा सके। हॉर्मुज से भारत के पश्चिमी तट (जैसे मुंबई या कांडला) तक पहुँचने में जहाजों को औसतन 2 से 3 दिन का समय लगता है। इस विवाद के कारण कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँच गई, जिसका लाभ रूस जैसे वैकल्पिक निर्यातकों को मिल रहा है।

दरअसल,विश्व के महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य (Straits) संकरे समुद्री मार्गों में से मलक्का, हॉर्मुज, बाब-अल-मंडेब और जिब्राल्टर सबसे प्रमुख हैं। ये वैश्विक तेल और वस्तु व्यापार (लगभग 25 प्रतिशत मलक्का से) को नियंत्रित करते हैं और समुद्री यात्रा का समय कम करते हैं। भारत के लिए अन्य वैकल्पिक समुद्री मार्गों की बात करें तो मलक्का जलडमरूमध्य इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है, जो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 25 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है। सुएज नहर जलमार्ग मिस्र में स्थित है, जो भूमध्य सागर और हिंद

महासागर को जोड़ता है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, खासकर यूरोप और मध्य पूर्व के साथ व्यापार के लिए। केप ऑफ गुड होप जलमार्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह जलमार्ग हार्मुज के अलावा एक वैकल्पिक मार्ग है, लेकिन यह अधिक लंबा और महंगा है। लोम्बोक जलडमरूमध्य इंडोनेशिया में स्थित है, जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यह जलमार्ग मलक्का जलडमरूमध्य के अलावा एक वैकल्पिक मार्ग है। लागत की दृष्टि से ये जलमार्ग हार्मुज की तुलना में अत्यंत महंगे और अधिक दूरी और लंबी यात्रा वाले हैं।

व्यापार और परिवहन के लिए हमेशा छोटे जलमार्ग सुविधाजनक और सस्ते रहते आए हैं। लंबी यात्राओं में समय और दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। मनुष्य ने अपने संघर्षों से इन प्राकृतिक जलडमरूमध्य मार्गों के अलावा पनामा नहर जैसे नए मनुष्य निर्मित जलडमरूमध्य मार्गों का निर्माण किया है। पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यह नहर पनामा देश में स्थित है। पनामा नहर के निर्माण से पहले, पोत परिवहन में कई दिक्कतें आती थीं। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक जाने के लिए जहाजों को दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर जाना पड़ता था, जिसे केप हॉर्न कहा जाता है। यह रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। इस लंबे रास्ते के कारण, जहाजों को अधिक समय और ईंधन की आवश्यकता होती थी, जिससे परिवहन की लागत बढ़ जाती थी। केप हॉर्न के आसपास का समुद्र बहुत अशांत और खतरनाक था, जिससे जहाजों को दुर्घटना का खतरा रहता था। पनामा नहर बन जाने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी इस नहर से होकर गुजरने पर तकरीबन 8000 मील (12,875 किमी) घट जाती है क्योंकि इसके न होने की स्थिति में जलपोतों को दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर चक्कर लगाते हुए जाना पड़ता था। पनामा नहर को पार करने में जलयानों को अब 8 घंटे का समय लगता है। नहर के माध्यम से जहाजों की आवाजाही से समय और ईंधन की बचत होती है, जिससे परिवहन की लागत कम हो जाती है। जहाजों की आवाजाही अधिक सुरक्षित हुई है, क्योंकि यह रास्ता खतरनाक समुद्रों की हलचलों से भी बचाता है। इसके साथ ही जहाजों की जल्दी आवाजाही से व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई है, क्योंकि यह माध्यम दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच कम समय में सीधा संपर्क प्रदान करता है।

वर्तमान परिस्थितियों में हमारे देश के संदर्भ में हॉर्मुज जलडमरूमध्य जलमार्ग का तेल, गैस आपूर्ति और क्रूड ऑयल आयात में महत्व बहुत बढ़ गया है। खाड़ी देशों की अशांति न सिर्फ उनके लिए बल्कि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन के लिए चिंताजनक है।

शिप्रा नदी में गंदे नाले मिलने पर कब लगेगी रोक?

सरोकार-1

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

एनजीटी द्वारा गठित इस जाँच दल ने पिछले दिनों दिनभर शिप्रा नदी के अलग-अलग जगहों पर जाकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और एक-एक जगह की वीडियोग्राफी भी करवाई। इस संयुक्त जाँच दल को निरीक्षण के दौरान अनेक गंभीर अनियमितताएं भी मिली। इसमें प्रमुख है - वाल्मीकि धाम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर के पीछे से नालों का गंदा पानी सीधा शिप्रा नदी में मिलता हुआ दिखा। इस जाँच दल ने गंगा घाट के पास 50 साल से अधिक पुराने और छायादार पेड़ों को मशीनों ने काटते हुए पाया। इसके साथ ह भेरूगढ़ क्षेत्र में दिल्ली दरवाजे के पास प्रिन्टिंग कारखानों का दूषित और जहरीला पानी भी नदी में मिलता हुआ जाँच दल ने पाया। इस जाँच दल ने शिप्रा नदी पर बन रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट और 7 फीट ऊँची सुरक्षा दीवार का भी निरीक्षण किया। जाँच दल के विशेषज्ञों को डर है कि बारिश के दिनों में यह दीवारें नदी के प्राकृतिक बहाव को नुकसान पहुंचा सकती है। एनजीटी के इस जाँच दल ने रामघाट, नृसिंग घाट, गऊघाट और त्रिवेणी घाट पर पानी की गुणवत्ता मानक स्तर से काफी नीचे पाई।

मोक्षदायिनी शिप्रा नदी अपनी बदहाल स्थिति पर आँसू बहा रही है। शिप्रा में अनेक जगह पर खुलेआम नालों का गंदा पानी मिल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। यह स्थिति आज नहीं बनी है। अनेक वर्षों से यही हालत बनी हुई है। शिप्रा नदी अपने मोक्षदाता का इंतजार कर रही है। अब देखना यह है कि कब उसका इंतजार खत्म होगा ?

पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के संयुक्त जाँच दल ने उज्जैन के विभिन्न घाटों का भ्रमण कर नदी की बदहाली अपनी आँखों से देखी। शिप्रा की दुर्दशा को लेकर श्री रमेशचन्द्र दुबे जी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने एक संयुक्त प्रशासनिक दल का गठन किया था। एनजीटी के संयुक्त जाँच दल में तीन सदस्य थे। इनके नाम हैं- सेन्ट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भोपाल के वैज्ञानिक डॉ. अनूप चतुर्वेदी, मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के रीजनल ऑफिस के श्री राजशेखर रेड्डी और एप्को के भोपाल के असिस्टेंट साईंटिफिक ऑफिसर डॉ. मनोज विश्वकर्मा।

एनजीटी द्वारा गठित इस जाँच दल ने पिछले दिनों दिनभर शिप्रा नदी के अलग-अलग जगहों पर जाकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया और एक-एक जगह की वीडियोग्राफी भी करवाई। इस संयुक्त जाँच दल को निरीक्षण के दौरान अनेक गंभीर अनियमितताएं भी मिली। इसमें प्रमुख है - वाल्मीकि धाम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर के पीछे से नालों का गंदा पानी सीधा शिप्रा नदी में मिलता हुआ दिखा।

इस जाँच दल ने गंगा घाट के पास 50 साल से अधिक पुराने और छायादार पेड़ों को मशीनों ने काटते हुए पाया। इसके साथ ह भेरूगढ़ क्षेत्र में दिल्ली दरवाजे के पास प्रिन्टींग कारखानों का दूषित और जहरीला पानी भी नदी में मिलता हुआ जाँच दल ने पाया। इस जाँच दल ने शिप्रा नदी पर बन रहे 29 किलोमीटर लंबे घाट और 7 फीट ऊँची सुरक्षा दीवार का भी निरीक्षण किया। जाँच दल के विशेषज्ञों को डर है कि बारिश के दिनों में यह दीवारें नदी के प्राकृतिक बहाव को नुकसान पहुंचा सकती है। एनजीटी के इस जाँच दल ने रामघाट, नृसिंग घाट, गऊघाट और त्रिवेणी घाट पर पानी की गुणवत्ता मानक स्तर से काफी नीचे पाई।

एनजीटी की टीम ने अपनी जाँच में पाया कि शिप्रा को स्वच्छ बनाने के तमाम दावों के बावजूद आज भी कई बड़े नाले और औद्योगिक ईकाईयाँ निरंतर अपनी गंदगी शिप्रा नदी में बहा रहे है। रूद्र सागर क्षेत्र का गंदा नाला उज्जैन का सबसे बड़ा और चर्चित नाला है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के दावों के बावजूद अक्सर बारिश और तकनीकी खराबी के दौरान इससे गंदा पानी सीधे रामघाट के समीप शिप्रा नदी में मिल जाता है। इसके साथ ही शमशान घाट चक्रतीर्थ और ऋमुक्तेश्वर मंदिर के समीप छोटे-बड़े कई नाले खुलेआम नदी में मिल रहे हैं। यहां के पानी का रंग काला पड़ चुका है।

शिप्रा नदी की सबसे बड़ी समस्या खान नदी है। इंदौर से आने वाली यह नदी पूरी तरह से प्रदूषित है। सरकार ने इसके लिए करीब 100 करोड़ रूपए की लागत से खान क्लोज डक्ट परियोजना बनाई थी। लेकिन रिसाव के कारण अक्सर खान नदी का जहरीला पानी त्रिवेणी संगम में शिप्रा में मिल जाता है। यहाँ पिछले अनेक सालों से मिट्टी का कच्चा बाँध बनाया जाता है, जो अक्सर हर बारिश में टूट जाता है और खान नदी का पूरा जहरीला पानी सीधा त्रिवेणी संगम पर शिप्रा नदी में मिल जाता है। कच्चे बाँध के भ्रष्टाचार के कारण आज तक यहाँ पक्का बाँध नहीं बन पाया है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन के ही निवासी है और यहीं से विधायक भी है। शिप्रा की दुर्दशा उनसे छिपी नहीं है। उनसे अपेक्षा है कि शिप्रा में अनेक जगहों पर खुलेआम मिल रहे गंदे नालों के पानी पर प्रभावी और स्थायी रोक लगाए, त्रिवेणी संगम पर कच्चे बाँध की जगह पक्का बाँध बनाये और मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को अपने नाम के अनुरूप बनी रहने दें। यदि मुख्यमंत्री जी ने शिप्रा नदी को स्वच्छ कर दिखाया तो यह उज्जैनवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सौगात होगी।

आर्थिक संकट से जूझ रही नपा बैतूल के लिए संजीवनी बनी लोक अदालत

नपा बैतूल ने वसूली का तोड़ा रिकॉर्ड, 93 लाख 65 हजार 956 रुपए टैक्स के लोगों ने किए जमा

एस. द्विवेदी, बैतूल। जिले भर की नगर पालिका कार्यालयों में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह अदालत आर्थिक रूप से जूझ रही नगर पालिकाओं के लिए काफी राहत भरी रही। इस बार लोक अदालत में नगर पालिका बैतूल ने वसूली का रिकार्ड कायम किया है। लोक अदालत में नगरपालिका ने करीब 93 लाख 65 हजार 956 रुपए की राजस्व वसूली की है। यह वसूली पिछले वर्ष की लोक अदालत से कहीं अधिक है। हालांकि नगरपालिका ने लोक अदालत के माध्यम से एक करोड़ से ऊपर के राजस्व वसूली का अनुमान लगाया था, लेकिन सुबह सर्वर डाउन होने और सर्वर की रफ्तार धीमी होने की वजह से यह वसूली कम हो पाई।

93 लाख से अधिक की हुई वसूली- राजस्व शाखा के वरिष्ठ राजस्व निरीक्षक ब्रजगोपाल परते, सुभाष प्रजापति एवं अखिल राय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार नगरपालिका ने बकाया राशि वाले करीब 2000 बकायादारों को डिमांड नोटिस जारी किये थे। नोटिस में कहा गया था कि पूरा टैक्स जमा करने पर सरचार्ज में छूट दी जायेगी। नगर के बकायदारों ने इन अदालतों में पहुंचकर करों का भुगतान किया और सरचार्ज का लाभ लिया। कर्मचारियों ने डोर-टू-डोर संपर्क करके बकायादारों को नोटिस भी दिए थे, जिसमें से 1525 लोगों ने टैक्स की राशि जमा की। गौरतलब कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरपालिका की कुल राजस्व डिमांड 11 करोड़ 67 लाख 80 हजार 790 रुपए है, इसके एवज में नगरपालिका ने फरवरी माह तक 5 करोड़ 10 लाख 15 हजार 659.54 रुपए की राशि वसूल कर ली थी, जोकि कुल डिमांड का मात्र 43.68 प्रतिशत था। जिसके बाद लोक अदालत के माध्यम से नगरपालिका ने लगभग 93 लाख 65 हजार 956 रुपए राजस्व वसूली की है। बहरहाल लोक अदालत के माध्यम से ही सही, लेकिन लोक अदालत में हुई राजस्व वसूली ने नगरपालिका के खजाने को भरने में काफी मदद की।

सबसे ज्यादा संपत्ति कर की वसूली

बैतूल नपा की राजस्व शाखा के सुभाष प्रजापति ने बताया कि लोक अदालत में सबसे अधिक संपत्ति कर की वसूली हुई है। इस बार लोक अदालत में 61,22,725 रुपए संपत्ति कर जमा हुआ है। इसी प्रकार जलकर के 26,73,954 रुपए और दुकान किराया राशि के 5 लाख 69 हजार 277 रुपए जमा किए गए है। कुल मिलाकर नगरपालिका ने लोक अदालत के माध्यम से 93 लाख 65 हजार 956 रुपए राजस्व की वसूली की है। वैसे राजस्व शाखा के अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वसूली में और बढ़ोत्तरी हो सकती थी, लेकिन बार-बार सर्वर बंद-चालू होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब नपा शेष बचे बकायादारों से राजस्व की वसूली के लिए पुन-नोटिस जारी कर वसूली करेगा। जिले की अन्य नगर पालिका में भी राजस्व वसूली की स्थिति ठीक रही।

कई विवादों का आपसी समझौते से निकाला हल

इधर लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया। लोक अदालत में कई ऐसे पारिवारिक विवाद भी सुलझे, जिसमें मनमुटाव के कारण परिवार लंबे समय से अलग-अलग रह रहे थे। लोक अदालत के माध्यम से इन टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ते हुए साथ रहने के लिए राजी किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के निराकरण के लिए कुल 27 खंडपीठों का गठन किया गया था। इन खंडपीठों में सडक दुर्घटना, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, मोटर व्हीकल, विद्युत चोरी, भूमि अधिग्रहण, ट्रैफिक चालान और श्रमिक मामलों सहित कई प्रकरणों की सुनवाई कर आपसी सहमति से निपटारा किया गया। कुटुंब न्यायालय में भी कई पारिवारिक मामलों का समाधान हुआ। इनमें मिलानपुर निवासी एक दंपति का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। पति-पत्नी के बीच विवाद के कारण दोनों करीब दो वर्षों से अलग रह रहे थे। लोक अदालत में समझाइश और आपसी सहमति के बाद दोनों के बीच सुलह हो गई और वे पुन-साथ रहने के लिए राजी हो गए। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित एक चेक बाउंस का मामला भी लोक अदालत में सुलझाया गया। एमपीईबी से जुड़े एक मामले में लेखीराम यादव का राजीनामा कराया गया। इन प्रकरणों के समाधान में अधिवक्ता हीरामन सूर्यवंशी, संजय पप्पी शुक्ला तथा सहयोगी अधिवक्ता अर्जुन लिखितकर, राजकुमार कांगले, आनंद खातरकर और दीपांशु का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

खंडेलवाल निवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान

दिवंगत पुत्री सुरभि को दी श्रद्धांजलि

बैतूल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बैतूल पहुंचे। उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निवास चंद्रमौली पहुंचकर उनकी दिवंगत पुत्री सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौहान निर्धारित कार्यक्रम से लगभग एक घंटे की देरी से बैतूल पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से बैतूल पहुंचे और सीधे गंज स्थित खंडेलवाल निवास गए। उन्होंने स्वर्गीय सुरभि खंडेलवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने खंडेलवाल परिवार से मुलाकात कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। शिवराज सिंह चौहान ने सुरभि के निधन को अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि खंडेलवाल परिवार इस कठिन समय से गुजर रहा है और वे इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। सुरभि खंडेलवाल के निधन के बाद से बैतूल में प्रदेश और केंद्र के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। इससे पहले, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शनिवार को बैतूल पहुंचकर खंडेलवाल परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कई मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी श्रद्धांजलि अर्पित करने बैतूल पहुंचे हैं। पिछले चार दिनों से बैतूल में वीआईपी आवाजाही बढ़ी है।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दिवंगत सुश्री सुरभि खंडेलवाल को दी श्रद्धांजलि

बैतूल। उप मुख्यमंत्री व लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश राजेन्द्र शुक्ल ने दिवंगत सुश्री सुरभि खंडेलवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रविवार को बैतूल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमन्त खंडेलवाल एवं उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

राजस्व मंत्री श्री वर्मा और पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री पटेल ने सुश्री सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि दी

बैतूल। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल ने रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल हेमन्त खंडेलवाल के निवास पहुंचकर दिवंगत सुश्री सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वर्गीय सुश्री सुरभि खंडेलवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की तथा विधायक श्री खंडेलवाल एवं उनके परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की।

किड्स जी का वार्षिक उत्सव संपन्न

वर्तमान परिपेक्ष्य के मुद्दों को नृत्य व नाटक से बच्चों ने बताया

बैतूल। प्री-स्कूल किड्स जी के वार्षिक उत्सव अनुभूति का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने अपनी आकर्षक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रंग-बिरंगे परिधानों में मनमोहक नृत्य, गायन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। नन्हे कलाकारों की मासूम अभिव्यक्ति और उत्साह ने उपस्थित अभिभावकों, अतिथियों और दर्शकों को प्रभावित किया। यह वार्षिकोत्सव ज़ी लर्न अधिकारियों सीनियर अकादमिक मैनेजर ट्विंकल साधवानी, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर ज़ी लर्न किरण कुमार नायर, डॉ.जया श्रीवास्तव, स्कूल संचालिका मंजुला पाठक एवं समस्त अभिभावकों, नन्हे सितारों, शाला शिक्षकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अभिभावकों की भागीदारी भी

कई सामान्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से माहौल को आनंदमई हो गया। वार्षिकोत्सव में बच्चों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नृत्य, नाटक द्वारा कई वर्तमान परिपेक्ष्य से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा, आत्मविश्वास और रचनात्मकता की सुंदर झलक देखने को मिली। संचालिका मंजुला पाठक ने अंत में सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

पंचायत और प्रशासन ने संभाली मेघनाथ बाबा मेला की व्यवस्थाएं

डंडार प्रतियोगिता और धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

बैतूल। तहसील चिचोली अंतर्गत ग्राम पंचायत चिरापाटला के ग्राम लोहारढाना में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 14 मार्च शनिवार को श्री मेघनाथ बाबा मेला श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत चिरापाटला द्वारा आयोजित इस मेले में क्षेत्र के ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी रही और धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के बीच पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण बना रहा। मेले के आयोजन में ग्राम पंचायत चिरापाटला की मुख्य भूमिका रही। सरपंच चिरापाटला, उपसरपंच चिरापाटला तथा समस्त पंचगण के सहयोग से मेला सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। मेले में विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद तथा जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और कार्यक्रम में सहभागिता की। मेले की व्यवस्थाओं के लिए तहसील चिचोली और जनपद पंचायत चिचोली के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक चिरापाटला द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चिचोली के निर्देशन में मेले की व्यवस्थाएं की गईं। तहसील चिचोली की ओर से तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी के निर्देशन में राजस्व निरीक्षक चिरापाटला, ड्यूटी में तैनात हल्का पटवारी तथा ग्राम कोटवार भी मौजूद रहे।

डंडार प्रतियोगिता रही मुख्य आकर्षण- मेघनाथ बाबा मेले के उपलक्ष्य में विशाल डंडार प्रतियोगिता का आयोजन रात्रि 8 बजे से 14 मार्च

2026 शनिवार तक किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न डंडार मंडलों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 11750 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 9750 रुपये, तृतीय पुरस्कार 7750 रुपये, चतुर्थ पुरस्कार 5750 रुपये, पंचम पुरस्कार 4750 रुपये, षष्ठम पुरस्कार 3750 रुपये और सप्तम पुरस्कार 2750 रुपये दिया गया। इसके साथ ही सांत्वना पुरस्कार के रूप में भी 2750 रुपये प्रदान किए गए और सभी टीमों को सम्मानित किया गया।

जनगणना और योजनाओं की दी जानकारी- मेले के दौरान राजस्व निरीक्षक चिरापाटला, हल्का पटवारी और ग्राम कोटवार द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित जनगणना 2026-2067 को सफल बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए मेले में मौजूद भूमका, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से सहयोग की अपेक्षा की गई।

नरवाई नहीं जलाने की दी समझाइश- मेले के दौरान किसानों को नरवाई नहीं जलाने की जानकारी भी दी गई और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से जागरूकता के साथ सहयोग करने की अपील की गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत चिरापाटला द्वारा आयोजित मेघनाथ बाबा मेला धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और प्रशासनिक व्यवस्था के समन्वय के साथ सम्पन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली।

भोपाल में हवाला के 55 लाख लूटे, 12 आरोपी गिरफ्तार

सट्टे के कर्ज में डूबे अकाउंटेंट ने रची थी साजिश; 35 लाख कैश बरामद

भोपाल (नप्र)। भोपाल के स्मार्ट सिटी रोड पर हवाला के 55 लाख रुपए लूटने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 35 लाख रुपए कैश, दो बाइक, एक एक्सेस स्कूटी, एक ऑटो और 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं। बाकी रकम और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, वारदात की साजिश एक अकाउंटेंट ने रची थी, जिस पर ऑनलाइन सट्टे के कारण कर्ज हो गया था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हवाला की रकम ले जाने वालों को निशाना बनाया और लूट की योजना बनाई।

हवाला के पैसों को बनाया निशाना- शामला हिल्स थाना क्षेत्र में 7 मार्च की रात करीब 9:30 बजे दो बदमाशों ने स्मार्ट सिटी रोड पर वाहन रोककर चाकू की नोक पर बैग छीन लिया था। बैग में 55 लाख 50 हजार रुपए थे। यह रकम हवाला के जरिए ले जाई जा रही थी। चूनाभट्टी निवासी दिव्यांग बरोट ने 8 मार्च को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

तीन-चार दिन पहले बनाई थी योजना- पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आरोपियों ने घटना से करीब तीन-चार दिन पहले योजना बनाई थी। इसके बाद पूरे रूट की रैकी की गई और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अपने मुखबिर नेटवर्क की मदद से आरोपियों तक पहुंची।

ऐसे दिया वारदात को अंजाम- 7 मार्च की रात हवाला की रकम लेकर जा रहे लोगों का आरोपियों ने पीछा किया। पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से उनका पीछा करते हुए स्मार्ट सिटी रोड पर आंचलिक विज्ञान केंद्र के पास वाहन अड़ाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद चाकू दिखाकर बैग में रखे करीब 55 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।

10 टीमों ने किया खुलासा- पुलिस आयुक्त संजय कुमार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में डीसीपी क्राइम अखिल पटेल और डीसीपी जोन-3 मयूर खंडेलवाल के पर्यवेक्षण में 10 टीमों का गठन किया गया। लगातार जांच और पतारसी के बाद पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

बच्ची का हाथ पकड़कर सिंधिया ने लगवाई एचपीवी वैक्सीन

गुना के म्याना अस्पताल में बोले- कुछ नहीं होगा, मैं रोज इंजेक्शन लगवाता हूं

गुना (नप्र)। गुना जिले के म्याना स्थित सिविल अस्पताल में रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक घबराई हुई बच्ची का हाथ पकड़कर उसे सर्वाइकल कैंसर से बचाव की एचपीवी वैक्सीन लगवाई और अस्पताल का निरीक्षण किया। वर्तमान में जिलेभर में 14 वर्ष तक की बच्चियों के लिए टीकाकरण और जागरूकता अभियान जारी है।

रविवार सुबह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जिले के म्याना इलाके के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर जायजा लिया और सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं। इसी दौरान टीकाकरण के लिए वहां पहुंची एक बच्ची से भी उन्होंने मुलाकात की।

नपा अध्यक्ष का कद कम करना चाहती है कांग्रेस..?

आखिर किसकी राह में रोड़ा बन सकते हैं अध्यक्ष

आमला। कहते हैं सियासत और तिजारत में ज्यादा फर्क नहीं होता है, यहां सब कुछ बनावटी और नकली होता है। कहा तो ये भी जाता है कि यहां जो दिखता है, दरअसल में वह होता नहीं है, कुछ ऐसा ही इन दिनों शहर कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है। शहर के सियासी पटल पर जिस तरह की चर्चाएं इन दिनों चल रही है, अगर उस पर भरोसा करें तो शहर में कांग्रेस अपने ही दल के और वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे का कद कम करने का प्रयास कर रही है और इन्हीं चर्चाओं के पीछे कई तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं। जिसके अनुसार कहीं तो कुछ ऐसा जरूर कांग्रेस में चल रहा है, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे का कद घटाने की कोशिश हो रही है। इसको एक ताजा मामले से भी समझा जा सकता है। दरअसल अभी हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस ने नगर पालिका में एक प्रदर्शन किया और नगर पालिका के विरोध में एक ज्ञापन भी दिया है। अब नपा में ही कांग्रेस का अध्यक्ष है, और कांग्रेस पार्टी ही नगर पालिका की नीतियों का विरोध कर

रही है, जिसको लेकर सियासी मैदान में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। यहां एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि जब शहर में ही कांग्रेस का कोई प्रदर्शन और धरना है, तो फिर इस प्रदर्शन से नगर पालिका अध्यक्ष को ही क्यों दूर रखा गया था या फिर जानबूझकर कांग्रेस ने नगर पालिका अध्यक्ष को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया।

क्या अध्यक्ष को पार्टी से अलग करने की कोशिश हो रही है- जैसा कि शहर में चर्चा है कि नपा आमला के अध्यक्ष नितिन गाडरे ही इस समय कांग्रेस में एकमात्र ऐसा चेहरा है, जिनके इर्द-गिर्द पिछले कुछ समय से कांग्रेस की पूरी राजनीति घूम रही है। वो भले ही इस समय नगर पालिका अध्यक्ष हो, किंतु उनका राजनीति में यकायक आना नगर पालिका अध्यक्ष तक का सफर करना और इलाके की राजनीति खासकर कांग्रेस के पटल पर अपनी सौम्य छवि स्थापित करके प्रसिद्धि पाना निश्चित ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा बाहर आ रही है कि नगर पालिका अध्यक्ष को एक दायरे में समेटा जा सकता है, और यह बात हम पार्टी में ही हो रही कुछ चर्चाओं के आधार पर कह रहे हैं। अब सच चाहे जो भी हो किंतु कहीं तो कुछ आग लगी है, ये धुआं बेवजह नहीं हो सकता।

कांग्रेस की सफाई

इस मौके पर हमने ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विजेंद्र भावसार से जब शहर में हो रही चर्चाओं के आधार पर उनसे बात की तो ब्लॉक अध्यक्ष का कहना था, कि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कांग्रेस के नगर पालिका में दिए गए प्रदर्शन के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष किसी निजी कार्यक्रम में शामिल थे, इस बात को बेवजह तूल दिया जा रहा है। यहीं ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनोज देशमुख ने बताया है, कि नगर पालिका में हमारे द्वारा किया गया प्रदर्शन और ज्ञापन नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ था, उस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कहीं कार्यक्रम में थे, इसलिए नगर पालिका अध्यक्ष को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था। अब इसके पीछे का सच चाहे जो हो किंतु शहर में उठ चर्चाओं के बाजार को कांग्रेस द्वारा डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। वही इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जब हमने इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे से बात की तो उन्होंने इस पूरी खबर की लगभग पुष्टि ही कर दी है, और कहा की उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, किंतु वह पार्टी के एक सच्चे सिपाही है और पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर शिविर लगाकर किया गया 675 बच्चों का टीकाकरण

सीहोर (निप्र)। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलेभर में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं एवं अनेक स्थानों पर प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत शिविर लगाकर टीकाकरण के साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसी क्रम में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के तहत जिले में 13 मार्च को आयोजित शिविरों में शून्य से एक वर्ष की आयु के 496 बच्चों तथा एक वर्ष से अधिक आयु के 179 बच्चों का टीकाकरण किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से हुई किरण के गृहस्थ जीवन की शुरुआत

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी और अनूठी योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक और धूमधाम से कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत जहां एक ओर सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से बेटियों का नया जीवन शुरू होता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इससे गरीब

और जरूरतमंद परिवारों को काफी राहत मिल रही है और माता-पिता बेटी के विवाह की चिंता से मुक्त हो रहे हैं। सीहोर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के सामूहिक विवाह सम्मेलन में ग्राम कालापीपल निवासी किरण अहिरवार भी परिणय सूत्र में बंधीं। किरण बताती हैं कि यह योजना उनके जैसी कई बेटियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के कारण उनका विवाह सम्मानपूर्वक और खुशियों के माहौल में सम्पन्न हुआ। सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता से उन्हें अपने नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने में भी मदद मिलेगी। बेटी किरण अहिरवार ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना ने गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया है।

यह योजना न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बना रही है बल्कि समाज में उनके सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

संक्षिप्त समाचार

जिले में शासन द्वारा निर्धारित नीति अनुसार ही उपार्जन कार्य सम्पादित किया जाए- कलेक्टर

रायसेन (निप्र)। रायसेन स्थित वन परिसर में शुक्रवार को कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूँ उपार्जन हेतु जिले में प्रस्तावित 190 उपार्जन केन्द्रों के लिए समिति प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं गुणवत्ता नियंत्रकों सर्वेयर का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सभी समिति प्रबंधकों, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा गुणवत्ता नियंत्रकों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति एवं अन्य निर्देशों का अक्षरतः पालन करते हुए उपार्जन कार्य सम्पादित किया जाए। सभी समिति प्रबंधकों को उपार्जन संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां भी उपार्जन प्रारंभ होने के पहले पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा पोर्टल संबंधी एवं गुणवत्ता प्रशिक्षणकों द्वारा गुणवत्ता संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त उपार्जन कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किए जाने एवं शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार खरीदी संबंधी समस्त कार्य, ऑनलाईन प्रविष्टि आदि निर्धारित दिन व समय पर किए जाने के बारे में जानकारी दी गई।

स्मार्ट विलेज परियोजना में मध्यप्रदेश से एकमात्र गांव जनकपुर का चयन

रायसेन (निप्र)। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 'विकसित भारत2047' के तहत 'स्मार्ट विलेज' परियोजना के अंतर्गत रायसेन जिले के जनकपुर गांव का चयन किया गया है। कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा गुरूवार को बाड़ी विकासखण्ड के चयनित ग्राम जनकपुर पहुंचकर परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष गुप्ता और सीएसआईआर के वैज्ञानिक भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कहा कि सीएसआईआर द्वारा स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत देश के कुल 06 गांवों का चयन किया गया है जिसमें जनकपुर गांव भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जनकपुर गांव, मध्यप्रदेश का एकमात्र गांव है जिसका चयन स्मार्ट विलेज परियोजना के लिए किया गया है। इस परियोजना के तहत जनकपुर में जीवन स्तर सुधारने, आजीविका बढाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सीएसआईआर-केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रूड़की को इस मिशन के लिए नोडल संस्था नामित किया गया है जो चयनित गांवों में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जनकपुर गांव को प्रयोगशालाओं, केन्द्र और राज्य सरकार तथा संबंधित हितधारकों का नेटवर्क मिलाकर एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने दिवंगत सुश्री सुरभि खंडेलवाल को दी श्रद्धांजलि

भोपाल ।उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने दिवंगत सुश्री सुरभि खंडेलवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल बैतूल में प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमन्त खंडेलवाल एवं उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

डॉक्टर सेवाभाव से मरीज का करें इलाज- उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

निजी मीडिया समूह के कार्यक्रम में रीवा शहर के डॉक्टर्स का किया सम्मान

भोपाल । उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि डॉक्टर को संवेदनशीलता के साथ मरीज का इलाज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि धरती में डॉक्टर भगवान के सामान हैं डॉक्टर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सेवाभाव से करें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पत्रिका समूह द्वारा आयोजित चिकित्सकों के सम्मान समारोह में शहर के डॉक्टर्स का सम्मान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि किसी मीडिया समूह द्वारा चिकित्सकों का रीवा में पहली बार इस तरह का सम्मान किया गया है। यह आयोजन सिद्ध करता है कि रीवा में डॉक्टर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। रीवा को मेडिकल हब बनाने का सपना सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब जीवन संकट में आता है तो केवल डॉक्टर के पास ही लोग जाते हैं। मेहनत से किये गये कार्य की जब बड़े सामाजिक स्तर पर सराहना मिलती है तो उत्साह भी बढ़ता है।

थाने से 100 मीटर दूर होटल में मिली अवैध शराब

एलपीजी सिलेंडर की जांच करने पहुंचे अफसर, आबकारी को बुलाकर कराई कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर चल रही किल्लत के बीच शुक्रवार शाम प्रशासन ने शहर में होटलों और भोजनालयों में छापेमार कार्रवाई की। जांच के दौरान बस स्टैंड के सामने स्थित पहलवान ढाबे से देसी-विदेशी शराब के 80 पाव (करीब 15 हजार रुपए कीमत) बरामद हुए। वहीं शहर के अलग-अलग होटलों से 7 अनाधिकृत गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ शहर के भोजनालयों, रेस्टोरेंट और होटलों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत उपयोग और भंडारण की जांच कर रहे थे। इसी दौरान कोतवाली थाने से करीब 100 मीटर दूर बस स्टैंड के सामने स्थित पहलवान ढाबे की जांच की गई। ढाबे में अवैध सिलेंडर तो नहीं मिले, लेकिन वहां बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब का जखीरा मिला। इसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। इसके बाद तत्काल आबकारी विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर कार्रवाई कराई गई।

काका श्री होटल में शराब पीते लोग भागे

पहलवान ढाबे के पास स्थित काका श्री होटल की भी जांच की गई। यहां शराब तो नहीं मिली, लेकिन कुछ लोग शराब पीते हुए मिले, जो टीम को देखकर मौके से भाग निकले। संयुक्त टीम ने जांच के दौरान कई होटलों से अनाधिकृत गैस सिलेंडर भी जब्त किए।

आबकारी एक्ट में ढाबा संचालक पर कार्रवाई

आबकारी उप निरीक्षक हेमंत चौकसे ने बताया कि पहलवान ढाबे से देसी और विदेशी शराब के 80 पाव जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 15 हजार रुपए है। मामले में ढाबा संचालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त तहसीलदार शक्ति सिंह राठौर, आरआई गजेंद्र जाटव और पुलिस टीम मौजूद रही।

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने कांग्रेस का प्रदर्शन

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग में हो रही कथित कालाबाजारी और सप्लाई संकट को लेकर शुक्रवार को कांग्रेसियों ने विरोध जताया। शाम करीब 4.30 बजे कलेक्ट्रेट गेट पर नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम जय सोलंकी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलेश बाथरे ने बताया कि ईरान-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे होटल, चाय दुकानों, पानी-बताशे और ठेला कारोबारियों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कई छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

घरेलू गैस कनेक्शन के लिए भी नहीं लग रहे ऑनलाइन नंबर

कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से घरेलू गैस कनेक्शन की बुकिंग के लिए भी ऑनलाइन नंबर नहीं लग पा रहे हैं। इससे आम लोगों की दैनिक जरूरतें प्रभावित हो रही हैं और रोजगार का संकट भी खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में छात्र घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। यदि टिफिन सेंटर और होटल बंद होते हैं तो इन छात्रों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो सकता है।

ये मांगें भी रखीं

कांग्रेसियों ने प्रशासन से मांग की कि स्थिति को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया जाए, निजी संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए और सभी प्रकार के शासकीय आयोजनों पर रोक लगाई जाए। इस दौरान अनोखी राजोरिया, पूर्व नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, अरुण दीक्षित, मीना वर्मा, अनुराग मलैया, शिवमंगल सिंह, अजीत विष्ट, कुसुम तोमर, कीर्ति मिश्रा, अजय शर्मा, हेमंत चौधरी, सूरज तिवारी, गुलाम हैदर, बलबीर चौहान सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

विदिशा जिले के 2.33 लाख किसानों के खातों में 46.68 करोड़ रुपये की राशि जमा

विदिशा (निप्र)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता राशि वितरण कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट शुक्रवार को जिले भर में देखा और सुना गया।

जिला मुख्यालय विदिशा पर यह कार्यक्रम एनआईसी के व्हीसी कक्ष में आयोजित किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में किसानों को राशि स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में विदिशा विधायक श्री मुकेश टंडन, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री वीर सिंह रघुवंशी, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा तथा कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर बताया गया कि योजना के अंतर्गत विदिशा जिले के कुल 2 लाख 33 हजार 445 किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से कुल 46 करोड़ 68 लाख 90 हजार रुपये की राशि अंतरित की गई है।

योजना से किसानों को खेती-किसानी के कार्यों में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ओ.पी. सनोडिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा योजना के लाभान्वित किसान उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराएं : कलेक्टर श्री सूर्यवंशी

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यानिकी , पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मछुआ कल्याण, जल संसाधन तथा श्रम विभाग को लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष फोकस करने की सख्त हिदायत दी। श्रमिकों के भुगतान से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जनपद पंचायत आमला, बैतूल, भैंसदेही, भीमपुर, चिचोली एवं मुलताई के अधिकारियों को प्राथमिकता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने वन विभाग से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सभी एसडीओ फॉरेस्ट को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही राजस्व विभाग की शिकायतों के समाधान के लिए सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को प्रत्येक प्रकरण की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन आदि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त सहकारिता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग को भी लंबित प्रकरणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

भूतड़ी अमावास्या पर आंवलीघाट पर व्यस्थाओं के लिए लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी

सीहोर (निप्र)। भूतड़ी अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आंवलीघाट पहुंचते है। आंवलीघाट श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार भूतड़ी अमावस्या के अवसर पर 17 मार्च से 19 मार्च तक अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारियों को 17 मार्च से प्रातः 08 बजे से आंवलीघाट पर उपस्थित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेशानुसार सीहोर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को आवंलीघाट पर पर्याप्त गोताखोर एवं मोटरबोट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

द्वितीय चरण का जनगणना प्रशिक्षण सम्पन्न

विदिशा (निप्र)। आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत जिला एवं चार्ज स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एसएटीआई कालेज के वी.वी. नाथू कंप्यूटर सेंटर में आयोजित किया गया था। अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी श्री अनिल कुमार डामोर ने बताया है कि जिला एवं चार्ज स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के अंतर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर जिला जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी, सभी अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) तथा जिला कार्यालय से एक जनगणना लिपिक शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र से चार्ज अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज अधिकारी एवं चार्ज कार्यालय से एक जनगणना लिपिक तथा नगरीय क्षेत्र से नगर पालिका और नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा संबंधित कार्यालय से एक जनगणना लिपिक प्रशिक्षण में भाग लिया है। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को जनगणना की प्रक्रिया, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई, ताकि आगामी जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संपन्न कराई जा सकें।

प्रस्तावित गाइड लाईन वर्ष 2026-27 के संबंध में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले के अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तावित गाइड लाईन वर्ष 2026-27 की दरों के निर्धारण हेतु कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति जिला रायसेन की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। जिसमें जिले की प्रचलित गाइड लाईन की कुल 2296 लोकेशन में से 1344 लोकेशन में मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई। शेष 952 लोकेशन में कोई मूल्य वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला पंचायत में सम्मान समारोह का आयोजन

बैतूल (निप्र)। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला पंचायत बैतूल के सभा कक्ष में 13 मार्च को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न पदाधिकारियों एवं सहयोगियों द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करना तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना था।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अक्षत जैन ने कहा कि आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। मिशन से जुड़ी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि समाज में एक नई पहचान भी बना

रही हैं। उन्होंने सभी सम्मानित प्रतिभागियों के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न विषयों के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के प्रतिनिधियों, मिशन के ब्लॉक स्टाफ तथा विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों को उनके कार्यक्षेत्र में मिशन गतिविधियों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के अनुभव भी साझा किए गए। कार्यक्रम का संचालन जिला परियोजना प्रबंधक श्री सतीश पवार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती इंदिरा महतो एवं मिशन से जुड़े विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष सावन सोनकर ने सुश्री सुरभि खंडेलवाल को दी श्रद्धांजलि

बैतूल (निप्र)। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री सावन सोनकर ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल के निवास पहुंचकर दिवंगत सुश्री सुरभि खंडेलवाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने विधायक श्री खंडेलवाल तथा उनके परिजनों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अर्थव्यवस्था का आधार उपभोक्ता है, उपभोक्ता की जागरूकता ही बाजार को गति और पहचान प्रदान करती है, हर उपभोक्ता का अपने अधिकारों को जानना और उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में सहभागी होना आवश्यक है।

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे का निर्णय

नवरात्रि मेले के दौरान मैहर स्टेशन पर 14 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव

भोपाल (नप्र)। नवरात्रि मेले के दौरान मैहर स्थित माता शारदा मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। भोपाल मंडल से गुजरने वाली 14 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर 5 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था 19 मार्च 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मैहर पहुंचते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों से गुजरने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों का अस्थायी हाल्ट प्रदान किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को सीधे मैहर पहुंचने में सुविधा मिल सकेगी।

विधवा से दुष्कर्म, केस दर्ज किया

इंदौर। हीरानगर थाना क्षेत्र में युवक ने विधवा महिला से पहले दोस्ती की। बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि कुछ साल पहले उसके पति का निधन हो गया था। इसके बाद उसकी पहचान सूरज काछी निवासी ग्राम मसुरहाई से हुई। कुछ दिन तक दोनों आपस में बात करते रहे। इसी बीच उनकी दोस्ती हो गई। आरोपी ने शादी का वादा किया और इसी बहाने उसे अपने कमरे पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

1636 बिना हेलमेट चालकों पर चालान

इंदौर। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। शुक्रवार को सुबह से रात तक चले अभियान में 1636 दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस केवल चालान ही नहीं काट रही है, बल्कि चौराहों पर अनाउंसमेंट कर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए भी जागरूक कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने पलासिया, विजयनगर, महू नाका, चाणक्यपुरी और भंवरकुआं सहित कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया। इसके अलावा नो-पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर भी कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग टीमों ने व्यस्त इलाकों में 137 वाहनों पर व्हील लॉक लगाकर कानूनी कार्रवाई की। अभियान के तहत यातायात जोन-1 में कालानी नगर, एयरपोर्ट रोड, बड़ा गणपति, इमली बाजार और बाणगंगा क्षेत्र में कार्रवाई हुई। जोन-2 में मालवा मिल, पाटनीपुरा, एलआईजी, रसोमा और विजयनगर में चेकिंग की गई। जोन-3 में एमजी रोड, आरएनटी मार्ग, जेलरोड, मधुमिलन और पलासिया क्षेत्र में कार्रवाई हुई। वहीं जोन-4 में सपना संगीता, राजवाड़ा, सराफा, जवाहर मार्ग और भंवरकुआं में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई।

प्लॉट सौदे में 2.44 करोड़ की ठगी

इंदौर। कनाड़िया थाना क्षेत्र में जमीन के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्लॉट दिलाने के नाम पर युवक से 2.44 करोड़ रुपए ले लिए, लेकिन न तो जमीन की रजिस्ट्री करवाई गई और न पैसे लौटाए गए। पुलिस ने फरियादी रोहित मारू की शिकायत पर तिलक नगर निवासी अजय सुराणा के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में बताया गया है कि अजय सुराणा और उसके भाई ने मिलकर रोहित को कीमती जमीन दिखाकर सौदा तय कराया था। प्लॉट का सौदा 4 करोड़ 50 लाख रुपए में तय हुआ था। भरोसा दिलाने के लिए मूल भू-स्वामी और उसके पति ने भी फरियादी को मौके पर ले जाकर प्लॉट दिखाए थे। इसी विश्वास के चलते रोहित मारू ने अलग-अलग किस्तों में कुल 2.44 लाख रुपए अजय सुराणा को दे दिए।

प्रदेश में एलपीजी संकट, सुबह से कतार में लगे लोग

इटारसी में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, नाले में पाइप डालकर चूल्हा जलाया, लगाए नारे

भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/उज्जैन (नप्र)। मध्य प्रदेश में रसोई गैस (एलपीजी) को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से होटलों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू गैस के लिए आम आदमी को धूप में घंटों पसीना बहाना पड़ रहा है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों से किल्लत और राहत की मिली-जुली तस्वीरें सामने आ रही हैं।

राजधानी का बुरा हाल: मैसेज आया, पर सिलेंडर नहीं- भोपाल के जहांगीराबाद और बोगदा पुल जैसे इलाकों में स्थिति गंभीर है। यहां शीबा खान एक हफ्ते से भटक रही हैं। उनके फोन पर 13 मार्च को डिलीवरी का मैसेज तो आ गया, लेकिन सिलेंडर घर नहीं पहुंचा। अब वे रिश्तेदारों के यहां खाना बनाने को मजबूर हैं।

वहीं मोहम्मद रियाज के घर 3 दिन से गैस नहीं थी। थक-हारकर उन्होंने नया इंडक्शन चूल्हा खरीदा है, ताकि परिवार भूखा न रहे।

कॉमर्शियल संकट- होटलों का बदला मेन्यू- 6 दिनों से प्रदेश के 50 हजार से ज्यादा होटल और रेस्टॉरेंट्स को कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिले हैं। भोपाल और इंदौर के कई होटलों ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया गया है। कई छोटी रेहड़ियां और ठेले पूरी तरह बंद हो गए हैं, जिससे दिहाड़ी दुकानदारों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है।

ग्वालियर और उज्जैन- प्रशासन ने संभाली कमान

- जहां एक तरफ मारामारी है, वहीं कुछ जिलों में प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने दावा किया है कि जिले में स्टॉक की कोई कमी नहीं है। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी बनाया है।
- उज्जैन में रविवार की छुट्टी होने के बावजूद महाकाल गैस एजेंसी को खोलकर सप्लाई जारी रखी गई। संचालक भगवान दास एरन के मुताबिक, घरेलू गैस की निरंतर सप्लाई की जा रही है, हालांकि कमर्शियल गैस के लिए अभी नए आदेशों का इंतजार है।
- वहीं पुरानी इटारसी में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ तंज भरा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और सिलेंडरों की कमी पर कटाक्ष करने के लिए नाले में गैस पाइप डालकर चूल्हा जलाया।

घरेलू गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश : रश्मि अरूण शमी

अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराने तथा एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने भी अधिकारियों को प्रतिदिन समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रेस ब्रीफ जारी कर नागरिकों से पैनिक बुकिंग नही करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में एजेंसी पर जाकर बुकिंग करने के स्थान पर डिजिटल माध्यम से बुकिंग करने की सलाह दी गयी है। ऑयल कंपनियों द्वारा मोबाइल एप, एसएमएस, व्हाट्सएप तथा आईवीआरएस कॉल द्वारा गैस बुकिंग की सुविधा प्रदान की गयी है। अतःउपभोक्ता बुकिंग के लिए इन डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें।

1357 सिलेंडर जप्त

एलपीजी की कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरूद्ध जारी निर्देशों के पालन में प्रदेश भर में लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में 1025 स्थानों पर कार्यवाही कर 1357 सिलेंडर जब्त किये गए तथा 08 प्रकरण में एफआईआर की गयी।

सिलेण्डर बुकिंग संबंधित शिकायत / सुझाव हेतु इन टोल फ्री नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है -

भारत गैस हेल्पलाइन नंबर - 1800-22-4344 (टोल फ्री)
इंडेन गैस कस्टमर केयर नंबर- 1800-2333-555 (टोल फ्री)
एचपी गैस कस्टमर केयर नंबर- 1800-2333-555 (टोल फ्री)

नवसंवत्सर 2083 का आगाज 20 मार्च से

ज्योतिषाचार्य ने ग्रह योगों के आधार पर युद्ध, महंगाई और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका जताई

भोपाल (नप्र)। हिंदू नववर्ष संवत 2083 का प्रवेश 19 मार्च 2026 को हो रहा है, लेकिन उदया तिथि में प्रतिपदा के क्षय होने के कारण नवसंवत्सर का आरंभ 20 मार्च, शुक्रवार से माना जाएगा। इस वर्ष का नाम रौद्र संवत्सर रहेगा। ज्योतिषाचार्य पं. विनोद गौतम के अनुसार वैशाख कृष्ण नवमी, 11 अप्रैल 2026 से दुर्मति नामक उपसंवत्सर प्रारंभ होगा, हालांकि संकल्प आदि में पूरे वर्ष रौद्र संवत्सर का ही प्रयोग किया जाएगा।

वर्ष के ग्रह पदाधिकारी और उनके प्रभाव- संवत 2083 के लिए ज्योतिषीय गणना के अनुसार वर्ष के दस पदाधिकारी निर्धारित किए गए हैं। इनमें राजा गुरु, मंत्री भौम (मंगल), सस्येश शुक्र, दुर्गेश चंद्र, धनेश गुरु, रसेश रवि, धान्येश बुध, नीरसेश गुरु तथा फलेश और मेघेश चंद्र हैं। इस प्रकार राजा गुरु के पास दो अतिरिक्त विभागों का स्वामित्व रहेगा, जबकि चंद्रमा को तीन विभागों की जिम्मेदारी मिलेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन ग्रह स्थितियों का असर देश-दुनिया की आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक परिस्थितियों पर दिखाई दे सकता है।

प्राकृतिक आपदा और महामारी की संभावना- ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस वर्ष आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ देशों में महामारी जैसे हालात बनने की संभावना भी ग्रह संकेत दे रहे हैं। चौपायों में रोग फैलने और पेयजल की कमी जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। श्रावण मास में पांच गुरुवार पड़ने से पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ने की संभावना जताई गई है, जबकि भारत के मध्य भाग में जनआंदोलन से अशांति की स्थिति बन सकती है।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर संभावित असर- ग्रह स्थिति के अनुसार पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर होने के संकेत बताए गए हैं। वहीं तुर्की और चीन जैसे देशों के लिए भी यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रह सकता है। अमेरिका में आंतरिक असंतोष और विद्रोह की आशंका जताई गई है, जबकि रूस और ईरान जैसे देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध मजबूत होने के संकेत बताए गए हैं। चीन और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के समाधान में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

रुद्र बीसी का 14वां वर्ष बताया गया- ज्योतिषाचार्य के अनुसार संवत 2083 तथाकथित रुद्र बीसी का 14वां वर्ष माना गया है। भृगु संहिता के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बीसी को 20-20 वर्षों के कालखंड में बांटा गया है। रुद्र बीसी की अवधि वर्ष 2012 से शुरू होकर 2032 तक मानी जा रही है।

युद्ध, आगजनी और वैश्विक तनाव की आशंका

ज्योतिषीय गणना के अनुसार वर्ष की शुरुआत में चतुर्ग्रही योग का प्रभाव रहेगा और मंगल-राहु का अंगारक योग आगजनी, विस्फोट और युद्ध जैसी स्थितियों के संकेत देता है। कई देशों में राजनीतिक असंतोष और राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ रोष बढ़ सकता है। मंगल-शनि की युति तापमान में वृद्धि और वर्ष के अंत तक महंगाई बढ़ने के संकेत दे रही है। वहीं सूर्य-शनि के षडाष्टक योग के कारण वाहन, रेल और हवाई दुर्घटनाओं की आशंका भी जताई गई है।

चश्मदीद बोला- गोलियां चलती रहीं, पुलिसकर्मी अंदर बैठे रहे

भोपाल के हमीदिया अस्पताल में शनिवार को फायरिंग हुई थी, टीआई ने कहा-अंदर का जिम्मा गार्ड का

भोपाल (नप्र)। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हुई फायरिंग की घटना को लेकर एक चश्मदीद सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शी हेमराज का कहना है कि जब अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर गोलियां चल रही थीं, उस समय अंदर मौजूद पुलिसकर्मी बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा सके।

हेमराज उज्जैन का रहने वाला है। उसके दामाद का विदिशा-सागर रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। गंभीर रूप से घायल दामाद को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे वह अपनी पत्नी के साथ इमरजेंसी गेट के पास खड़ा था। हेमराज ने बताया-एक्टिवा सवार तीन युवक पहुंचे। एक के हाथ में चाकू, दूसरे के हाथ में पिस्टल थी। तीसरा युवक गाड़ी पर बैठा रहा। दोनों इमरजेंसी गेट के पास पहुंचे और वहां खड़े व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब तीन राउंड फायर के बाद गालियां देते हुए फरार हो गए।

पुलिसकर्मी इमरजेंसी वार्ड के अंदर मौजूद थे- हेमराज के मुताबिक, जिस व्यक्ति पर गोलियां चलाई गईं, उसे अस्पताल के गार्ड्स अंदर ले गए। उस समय इमरजेंसी वार्ड के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन वे बाहर नहीं निकले।

एमपी के 22 लाख पेंशनर्स को झटका

केंद्र का सहायता राशि बढ़ाने से इनकार, नीति आयोग की सिफारिश के बावजूद वृद्धि नहीं

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के करीब 22.5 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए दिल्ली से निराशाजनक खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के इस फैसले का सीधा असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा, जो महंगाई के इस दौर में आर्थिक मदद बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि नीति आयोग और अन्य मूल्यांकन अध्ययनों ने सहायता राशि में वृद्धि करने और भुगतान प्रणाली को मजबूत करने की सिफारिश की थी। अध्ययनों में यह भी पाया गया कि लाभार्थी इस पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी अनिवार्य जरूरतों के लिए कर रहे हैं। इसके बावजूद, सरकार ने फिलहाल राशि बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

भोपाल नगर निगम घोटाला- अपर आयुक्त सेवतकर को हटाया

लोकायुक्त ने की थी एफआईआर, बजट से पहले कमिश्नर ने हटाकर दूसरे को सौंपा वित्त विभाग

भोपाल (नप्र)। भोपाल नगर निगम की वित्त एवं लेखा शाखा में अपर आयुक्त गुणवंत सेवतकर को कमिश्नर संस्कृति जैन ने हटा दिया। लोकायुक्त ने उन पर एफआईआर दर्ज की थी। उनकी जगह अपर आयुक्त मुकेश शर्मा को प्रभार सौंपा गया है। कुछ दिनों में नगर निगम का बजट पेश होना है। जिसे बनाने का जिम्मा सेवतकर के पास ही था।

बता दें कि नगर निगम में बिना काम कराए फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए निकालने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने

शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की थी। टीम ने निगम के डाटा सेंटर समेत कई शाखाओं में छापेमारी कर पिछले करीब 10 साल के दस्तावेज और सर्वर डाटा जब्त कर लिया था। इस मामले में सेवतकर समेत अन्य पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर के बाद शनिवार को कमिश्नर जैन ने सेवतकर को हटाने की कार्रवाई की।

कोर्ट से सर्च वारंट लेकर की थी छापेमारी- निगम में फर्जी भुगतान की शिकायत नवंबर 2025 में लोकायुक्त को मिली थी। प्रारंभिक जांच में तथ्य सही पाए जाने पर 9 मार्च को आयुक्त गुणवंत सेवतकर के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेकर छापेमारी की गई थी।

सर्वर समस्या से राहत, इंदौर में गैस सिलेंडर की मैन्युअल बुकिंग शुरू

शहर में प्रतिदिन लगभग 24 से 25 हजार सिलिंडरों का वितरण

इंदौर। शहर में रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग में आ रही तकनीकी समस्या के कारण परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब गैस एजेंसियों पर मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शुक्रवार से शहर की 52 गैस एजेंसियों में उपभोक्ता सीधे पहुंचकर सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें घर तक सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी।

पिछले कुछ दिनों से गैस बुकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले दूरभाष और मोबाइल माध्यमों पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण सर्वर बार-बार बंद हो रहा था। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ता सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पा रहे थे। देश के कई शहरों में भी इसी तरह की समस्या सामने आई है, जहां बुकिंग के लिए कॉल और संदेशों की संख्या सामान्य से कई गुना बढ़ने के कारण व्यवस्था प्रभावित हुई। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गैस एजेंसियों को मैन्युअल बुकिंग की अनुमति दी है, ताकि उपभोक्ताओं को आवश्यक रसोई गैस समय पर मिल सके।

ज्यादा वाहन और हॉकर लगाए

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निर्देश पर गैस एजेंसियों ने वितरण व्यवस्था भी मजबूत की है। एजेंसियों ने अतिरिक्त वाहन और हॉकर लगाए हैं ताकि बुकिंग के बाद सिलिंडर जल्द से जल्द उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाया जा सके। आमतौर पर शहर में प्रतिदिन लगभग 24 से 25 हजार सिलिंडरों का वितरण होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए अब यह संख्या बढ़ाकर लगभग 27 से 28 हजार प्रतिदिन कर दी गई है।

घरेलू सिलेंडर का दुरुपयोग

खाद्य विभाग ने निरीक्षण अभियान भी तेज कर दिया है। महू और इंदौर के कुछ भोजनालयों में व्यावसायिक सिलिंडर की जगह घरेलू सिलेंडर का उपयोग पाए जाने पर कार्रवाई की गई। जांच दल ने नौ प्रकरण दर्ज करते हुए 32 सिलिंडर जब्त किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि शहर में रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में आशंका के कारण बुकिंग की संख्या अचानक बढ़ गई, जिससे सर्वर पर दबाव बढ़ा और तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई। स्थिति सामान्य करने के लिए निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

शहर का यातायात सुधारने का काम 12 विशेष पेट्रोलिंग टीमों को सौंपा

ट्रैफिक दबाव, ख़राब पार्किंग और लापरवाह चालकों पर नजर

इंदौर। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब चार जोनों में 12 विशेष पेट्रोलिंग टीमें लगातार गश्त करेंगी। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य व्यस्त मार्गों, प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अव्यवस्थित और अवैध पार्किंग पर नियंत्रण रखना और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना है।

शनिवार को डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारियों का जायजा लिया। इस दौरान अतिरिक्त डीसीपी, सहायक पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी भी मौजूद थे। उन्होंने पेट्रोलिंग और व्हील लॉक टीमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही 8 अतिरिक्त पेट्रोलिंग टीमों का गठन भी किया गया। ट्रैफिक के चारों जोनों में 2-2 व्हील लॉक और पेट्रोलिंग टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें

प्रत्येक टीम में 4 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। ये टीमें अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में घूमकर ट्रैफिक दबाव, अव्यवस्थित पार्किंग और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखेंगी।

बाजारों में सक्रिय निगरानी- पेट्रोलिंग टीमों द्वारा मुख्य मार्गों, व्यस्त बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निरंतर गश्त की जाएगी। पीए प्रणाली, बॉडी कैमरा, क्रेन और सपोर्ट वाहन, व्हील लॉक और चालानी मशीनों की सहायता से अवैध पार्किंग, फुटपाथ पर वाहन खड़े करना और सड़क पर वाहन खड़े कर ट्रैफिक बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में पहले वाहन चालकों को समझाइश और चेतावनी दी जाती है।

व्हील लॉक और चालान- इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ व्हील लॉक और क्रेन के माध्यम से चालानी कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही पीए सिस्टम के जरिए जनता को यातायात नियमों का पालन करने और निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की अपील की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की सतत कार्रवाई के परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुगम हुई है और आम जनता को राहत मिली है। आगामी दिनों में भी विशेष पेट्रोलिंग और सख्त कार्रवाई विभिन्न इलाकों में जारी रहेगी।